घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 288- गुरूवार 20- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला....13,041 करोड़ की 5 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी, बिहार में बनेगा 4-लेन हाईवे

नई दिल्ली,19 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी पांच महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 13,041 करोड़ रुपये है। सरकार के फैसले में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के साथ बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली बड़ी परियोजना भी शामिल है। इन योजनाओं से यातायात क्षमता बढ़ने और क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

बिहार को मिली 3,591 करोड़ रुपये की बड़ी परियोजना

कैबिनेट बैठक में बिहार के लिए मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा 4-लेन हाईवे कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी गई है। एनएच-22 से जुड़े इस प्रोजेक्ट पर करीब 3,591 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लगभग 83 किलोमीटर लंबे इस हाईवे से मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिलों के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ व्यापार और परिवहन गतिविधियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।

30 महीने में पूरा होगा 4-लेन हाईवे

सरकार के अनुसार,बिहार की इस सड़क परियोजना का निर्माण हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल यानी HAM के तहत किया जाएगा। परियोजना में फ्लेक्सिबल पेवमेंट तकनीक का इस्तेमाल होगा और इसे करीब 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत सात प्रमुख पुल, तीन रेलवे ओवरब्रिज और छह व्हीकुलर अंडरपास बनाए जाएंगे। इससे सड़क मार्ग पर यातायात को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

पुलों का भी होगा बड़े स्तर पर निर्माण : खड़गपुर-भद्रक परियोजना के तहत रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई पुलों का निर्माण किया जाएगा। योजना में दो मेगा ब्रिज, 41 बड़े पुल और 169 छोटे पुल शामिल हैं। चौथी लाइन बनने के बाद इस रेल कॉरिडोर पर ट्रेनों की आवाजाही के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी। इससे क्षेत्र में माल ढुलाई और यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

स्वर्णमुखी नदी पर बनेगा 360 मीटर मेगा ब्रिज : गुम्मिडीपुंडी-गुडूर परियोजना में स्वर्णमुखी नदी पर करीब 360 मीटर लंबा मेगा ब्रिज भी बनाया जाएगा। इस ब्रिज के निर्माण से रेल संचालन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों और यात्रियों की संख्या को देखते हुए इस रेल कॉरिडोर की क्षमता बढ़ाना जरूरी है। नई लाइनें भविष्य में माल ढुलाई को भी अधिक सुगम बना सकती हैं।

रेलवे नेटवर्क के विस्तार पर भी सरकार का फोकस

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच परियोजनाओं में चार रेलवे लाइन विस्तार योजनाओं को भी मंजूरी दी है। इनमें खड़गपुर-भद्रक (रानीताल) चौथी लाइन,भद्रक-हरिदासपुर चौथी लाइन,गुम्मिडीपुंडी-गुडूर तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक-पारादीप तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेलवे की क्षमता बढ़ाने और माल तथा यात्री परिवहन को अधिक प्रभावी बनाना है।

खड़गपुर-भद्रक चौथी लाइन पर 3,352 करोड़ खर्च

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, खड़गपुर से भद्रक के बीच चौथी रेलवे लाइन विकसित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। यह रेल मार्ग बालेश्वर और रुपसा से होते हुए भद्रक तक जाएगा। लगभग 173 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 3,352 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे ओडिशा के तटीय क्षेत्र में रेल परिवहन की क्षमता और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

भद्रक-हरिदासपुर चौथी लाइन को भी मंजूरी

कैबिनेट ने भद्रक-हरिदासपुर चौथी रेलवे लाइन परियोजना के लिए 1,583 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह परियोजना ओडिशा में रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अतिरिक्त रेल लाइन उपलब्ध होने से मौजूदा मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने और भविष्य की परिवहन जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

गुम्मिडीपुंडी-गुडूर रेल कॉरिडोर का होगा विस्तार

गुम्मिडीपुंडी-गुडूर रेलवे परियोजना के तहत तीसरी और चौथी लाइन विकसित की जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,229 करोड़ रुपये है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस कॉरिडोर के आसपास मशीनरी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से जुड़ी नई औद्योगिक इकाइयां विकसित हो रही हैं। ऐसे में अतिरिक्त रेल लाइन औद्योगिक और यात्री परिवहन दोनों के लिए उपयोगी होगी।

कटक-पारादीप रेल लाइन का भी विस्तार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कटक-पारादीप रेल कॉरिडोर की तीसरी और चौथी लाइन को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,286 करोड़ रुपये है। पारादीप क्षेत्र की औद्योगिक और बंदरगाह गतिविधियों को देखते हुए इस रेल विस्तार का महत्व काफी अधिक है। अतिरिक्त लाइनें बनने से माल परिवहन की क्षमता बढ़ने और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।

देहरादून-ऋषिकेश हाईवे पर भीषण हादसा...4 की मौत,3 गंभीर घायल

नई दिल्ली,19 अगस्त 2026। उत्तराखंड के देहरादून जिले में बुधवार को देहरादून-ऋषिकेश हाईवे (एनएच-07) पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मणिमाई मंदिर के पास हुए इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचा और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई शुरू की।

देहरादून से रोहतक जा रहे थे सात लोग

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मारूति ईको कार में कुल सात लोग सवार थे। सभी लोग उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हरियाणा के रोहतक की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि कार जैसे ही मणिमाई मंदिर के नजदीक पहुंची, उसी दौरान वह सड़क किनारे खड़े एक महिंद्रा मैक्स वाहन से जा भिड़ी।

टक्कर के बाद मची चीख-पुकार

हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार कई लोग वाहन के अंदर ही फंस गए। टक्कर के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव में मदद की। दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम और राहत-बचाव कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया।

कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया

राहत-बचाव दल ने दुर्घटनाग्रस्त ईको कार में फंसे लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। घायलों को तत्काल देहरादून के निजी अस्पतालों में उपचार के लिए भेजा गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक,हादसे में कार चालक समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, गंभीर रूप से घायल दो अन्य लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

डाबर के बाद Zandu समेत इन कंपनियों पर शिकंजा,'100%' दावों पर सख्ती...

नई दिल्ली,19 अगस्त 2026। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य और पेय पदार्थों की पैकेजिंग, लेबल और विज्ञापनों में किए जाने वाले '100%' दावों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। कंपनियां अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए '100% Pure', '100% Natural' और इसी तरह के दावों का इस्तेमाल करती हैं। खाद्य नियामक का मानना है कि इस तरह की भाषा कई बार उपभोक्ताओं के बीच गलत धारणा पैदा कर सकती है और हर उत्पाद के लिए ऐसे दावों को पूरी तरह वैज्ञानिक या निर्धारित मानकों के आधार पर साबित करना आसान नहीं होता।

ग्राहकों को भ्रमित कर सकते हैं ऐसे दावे : फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार, किसी खाद्य उत्पाद पर '100% प्योर' या '100% नैचुरल' लिखा होने से उपभोक्ता यह मान सकता है कि उत्पाद में किसी भी तरह की मिलावट नहीं है या उसकी सामग्री पूरी तरह प्राकृतिक है। हालांकि, किसी उत्पाद की पूरी तरह शुद्ध या प्राकृतिक होने की ऐसी व्यापक पुष्टि अलग-अलग परिस्थितियों में जटिल हो सकती है। इसलिए खाद्य कंपनियों को अपने दावों की भाषा में स्पष्टता और प्रमाणिकता बनाए रखने की जरूरत है।

पांच कंपनियों ने हटाए '100%' वाले दावे : फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कार्रवाई और निर्देशों के बाद पांच कंपनियों ने अपने उत्पादों और प्रचार सामग्री से ऐसे '100%' दावे हटाने पर सहमति जताई है। इनमें BONN BISCUITS, Zandu Honey, AMWAY INDIA और JUZA FOODS समेत पांच कंपनियां शामिल हैं। खाद्य नियामक लगातार कंपनियों की पैकेजिंग, लेबलिंग और विज्ञापन सामग्री की निगरानी कर रहा है, ताकि उपभोक्ताओं तक सही और सत्यापित जानकारी पहुंच सके।

पैकेजिंग और विज्ञापनों पर भी नजर : खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का कहना है कि कंपनियों द्वारा उत्पादों से संबंधित किए जाने वाले दावे स्पष्ट, सटीक और जांच के आधार पर साबित किए जा सकने वाले होने चाहिए। किसी खाद्य वस्तु की गुणवत्ता या विशेषता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने वाली भाषा उपभोक्ताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से पैकेट पर लिखे दावों के साथ-साथ विज्ञापनों और अन्य प्रचार सामग्री पर भी निगरानी रखी जा रही है।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक में फैसला...वंदे मातरम के दो ही पैरा गाएगी कांग्रेस

कहा...वंदे मातरम् और राष्ट्रगान बीजेपी के लिए राजनीतिक मुद्दे

नई दिल्ली,19 अगस्त 2026। नई दिल्ली के इंदिरा भवन में बुधवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। बैठक में पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 88 नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने वंदे मातरम् को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी 1937 में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लिए गए फैसले का पालन करेगी। इसके तहत पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के केवल दो अंतरे गाए जाएंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि वंदे मातरम् और राष्ट्रगान कांग्रेस के लिए भावनात्मक मुद्दे हैं,जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीतिक मुद्दे हैं।

मानसून सत्र में सरकार बैकफुट पर रही

वेणुगोपाल ने कहा...बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के साथ-साथ छात्रों से जुड़े मुद्दों और राम मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित गड़बड़ी को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। हमारा ध्यान तीन-चार मुद्दों पर है। पहला मुद्दा पेपर लीक का है। देश के लोगों ने इसके खिलाफ जो आंदोलन किया और सरकार ने जिस तरह उस आंदोलन से निपटा, उस पर चर्चा हुई। साथ ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने माना कि संसद का मानसून सत्र विपक्ष के लिए सफल रहा और केंद्र सरकार बैकफुट पर रही।

अरुणाचल में चीनी घुसपैठ पर भी चर्चा : वेणुगोपाल ने कहा कि बैठक में अरुणाचल प्रदेश में 'चीनी घुसपैठ' के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पार्टी की चिंता बैठक में रखी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि महिलाओं के लिए आरक्षण लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या के आधार पर लागू किया जाए।

जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री से माफी मांगने को कहा : प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जयराम रमेश ने उत्तराखंड में खडगे के कार्यक्रम के बाद हुए 'शुद्धिकरण' को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश से माफी मांगने की मांग की।

छात्रों के लिए 800 शहरों में की जाएंगी सभाएं...

वेणुगोपाल ने कहा...चंदा चोरी देश के लोगों के बीच चिंता का गंभीर मुद्दा है। यह लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है। जिन्होंने लोगों को बांटने के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल किया, वे अब बेनकाब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी छात्रों की मांगें उठाते रहेंगे। इसके तहत 800 शहरों में सभाएं की जाएंगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पार्टी के मुख्यमंत्रियों से शिक्षा विशेषज्ञों के साथ काम करने को कहा है। उनसे शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए रोडमैप तैयार कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

बिहार : छात्रों के समर्थन में आरजेडी का लोकभवन मार्च...वाटर कैनन चलाई गई प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस पर बोतलें फेंकीं,हिरासत से छूटे तेजस्वी

पटना,19 अगस्त 2026। बिहार के सीवान में छात्र आंदोलन के दौरान एके-47 से फायरिंग के मामले को लेकर तेजस्वी यादव बुधवार को सड़क पर उतरे। उन्होंने पटना में जेपी गोलंबर से लोकभवन तक मार्च निकाला। करीब 5 किलोमीटर लंबे मार्च में उनके साथ करीब 5 हजार समर्थक मौजूद रहे। समर्थकों के साथ तेजस्वी डाकबंगले पर लगाई बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गए। इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। इसके बाद तेजस्वी को हिरासत में लिया गया। हालांकि, एक घंटा बाद उन्हें छोड़ दिया। तेजस्वी ने कहा कि मैं जेल से डरने वाला नहीं हूं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ था। जो सत्ता में आया है, उसका जाना तय है। कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस के ऊपर पानी की बोतलें भी फेंकीं। कुछ कार्यकर्ता लकड़ी कीएके-47 लेकर पहुंचे थे।

तेजस्वी बोले- रोजगार देने के मुद्दे पर संघर्ष जारी रहेगा

थाने से बाहर आने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, 'जब तक मुख्यमंत्री जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे पूरी घटना का वक्तव्य नहीं देंगे और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया ये लोगों के सामने नहीं रखेंगे, छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, बेरोजगारी खत्म नहीं होती हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ' आरजेडी के राजभवन मार्च पर आईजी पटना जितेंद्र राणा ने कहा, 'राजभवन मार्च का कार्यक्रम था जो गांधी मैदान से शुरू हुआ था, यहां आईटी गोलंबर पर आकर मार्च समाप्त हो गया है। प्रतिनिधिमंडल को लोकभवन से समय मिला है और वे मिलने जाएंगे। जो भी मांगे हैं, उनको वहां रखेंगे। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनमें से कुछ लोग लोकभवन के लिए जा चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश...बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं माता-पिता, उन्हें सम्मान और सुरक्षा देना सभ्य समाज की पहचान

नई दिल्ली,19 अगस्त 2026। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सीनियर सिटीजन्स अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बढ़ती उम्र का मतलब असुरक्षा या अपमान नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवनभर गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी पलट दिया,जिसमें बेटे और बहू को मकान से बेदखल करने के ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश को रद्द किया गया था। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों की गरिमा के लिए ट्रिब्यूनल के पास बच्चों को संपत्ति से निकालने का आदेश देने का अधिकार है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि कानून का मकसद बुजुर्गों की गरिमा और सुरक्षा तय करना है। सभ्य समाज का स्तर अक्सर इस बात से तय होता है कि वह अपने बुजुर्गों को कितनी गरिमा, सम्मान और सुरक्षा देता है। यह

मामला लखनऊ के विकास नगर निवासी रवि कांत गुप्ता की अपील से जुड़ा था। गुप्ता ने 5 जून 2022 को अपने बेटे को मकान से निकालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दिया था। यह मकान उनकी खुद की खरीदी हुई संपत्ति थी। मामला तब सामने आया, जब गुप्ता की 81 साल की मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। एसडीएम ने 15 नवंबर 2022 को बेटे की बेदखली का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने 9 अगस्त 2023 को इसे बरकरार रखते हुए बेटे और बहू को मकान खाली करने का निर्देश दिया। बेटे और बहू ने एसडीएम और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने कहा था कि 2007 का कानून बुजुर्गों को अपनी संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने का अधिकार नहीं देता। इसके बाद दोनों आदेश रद्द कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश में दखल देकर गलती की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण और सुरक्षा के लिए जरूरी होने पर ट्रिब्यूनल बेदखली का आदेश दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि एक्ट की धारा 7 के तहत ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं और धारा 8 उन्हें सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां देती है। वहीं, धारा 27 सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है।

महुआ मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी सेना पर विवादित टिप्पणी का मामला

नई दिल्ली,19 अगस्त 2026। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कृष्णानगर की अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। मामला भारतीय सेना और अन्य संवेदनशील मुद्दों को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा बताया जा रहा है। अदालत ने सांसद को मामले की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई बार समन जारी होने के बावजूद उनके अदालत में पेश नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। मामले की शुरुआत एक इंटरव्यू में भारतीय सेना को लेकर महुआ मोइत्रा की कथित विवादित टिप्पणियों से हुई। इन बयानों को लेकर कृष्णानगर की ACJM अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू की और सांसद को निर्धारित तारीखों पर उपस्थित होने के निर्देश दिए। अदालत के सूत्रों के मुताबिक, कई बार आदेश और समन जारी होने के बाद भी उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं हुई। महुआ मोइत्रा पर सोशल मीडिया के जरिए भारतीय सेना के जवानों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया गया है।

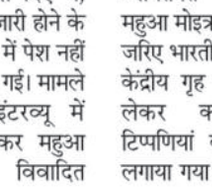

जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलन खत्म....झारखंड सरकार को दो महीने का अल्टीमेटम जांच नहीं हुई तो फिर रांची में जुटेंगे छात्र

रांची,19 अगस्त 2026। झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ कई दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया है। जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने मंगलवार को आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया। इससे एक दिन पहले सोमवार देर शाम देवेंद्रनाथ गुट ने भी अपना आंदोलन खत्म कर दिया था। अब छात्रों ने राज्य सरकार को मामले की उच्चस्तरीय जांच पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया है। मंच ने साफ कर दिया है कि अगर तय समय में निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हुई, तो छात्र फिर बड़ी संख्या में रांची पहुंचेंगे और इस बार सीबीआई जांच उनकी मुख्य मांग होगी।

तमिलनाडु में विधायकों को नई कार,75 हजार भत्ता मिलेगा

मुख्यमंत्री विजय की विधानसभा में घोषणा...दूध खरीद मूल्य 38 से बढ़ाकर 41 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा

चेन्नई,19 अगस्त 2026। तमिलनाडु विधानसभा में बुधवार को अनुदान मांगों पर चर्चा के तीसरे दिन मुख्यमंत्री विजय ने विधायकों और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की। उन्होंने सभी विधायकों को निर्वाचन क्षेत्रों के दौरे और जनसेवा के लिए सरकार की ओर से वाहन उपलब्ध कराने का ऐलान किया। इसके अलावा दूध खरीद मूल्य बढ़ाने, चेन्नई के पेरम्बूर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने, मुख्यमंत्री चिकित्सा बीमा की सीमा बढ़ाने और राज्य में सात नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की। सहायक की नियुक्ति के लिए 25 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वाहन के ईंधन और रखरखाव के लिए 75 हजार रुपये मासिक वाहन भत्ता दिया जाएगा। यह घोषणा पिछले सप्ताह विदुथलाई चिरुथैगल काची के विधायक ज्योतिमणि की उस मांग के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने विधायकों को निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने एक अन्य घोषणा में कहा कि राज्य की करीब 8,800 सहकारी समितियों से जुड़े 3.16 लाख दूध उत्पादकों से प्रतिदिन लगभग 34 लाख लीटर दूध खरीदा जा रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन करीब 31 लाख लीटर दूध आविन के माध्यम से उत्पादित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए दूध की खरीद कीमत 38 रुपये से बढ़ाकर 41 रुपये प्रति लीटर की जाएगी।

संपादकीय

भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता

भारतीय ज्ञान परंपरा पर अध्ययन, अध्यापन और शोध की प्रक्रिया भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रारंभ हो गई है। कई विश्वविद्यालयों में इस विषय पर अध्ययन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और उच्च शिक्षण संस्थानों में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं।

यह पहल हमें अपने सोच,विचार और मानसिकता में विद्यमान औपनिवेशिक प्रभावों से मुक्ति दिलाने में मदद करेगी। अपनी ज्ञान परंपरा की खोज न केवल औपनिवेशिक शासन में रहे देशों में हो रही है,बल्कि चीन, जापान जैसे कई देश भी अपने राष्ट्रीय स्व को ज्ञान से जोड़ते हुए अपनी जड़, जमीन और संस्कृति में उपजे ज्ञान,मेधा,दक्षता और तकनीकी को अपनी आधुनिकता में शामिल कर रहे हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध,अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया भारत में विलंब से शुरू हुई है। इसे आजादी के बाद से ही आरंभ हो जाना चाहिए था, लेकिन यह संतोषजनक है कि शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देखरेख में यह प्रक्रिया अब लगातार आगे बढ़ रही है। इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां भी हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा मात्र कोई विषय न होकर एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिससे हम अपने सभी विषयों और ज्ञान की अनुषंगी इकाइयों को समझ सकते हैं। यह एक दार्शनिक और सैद्धांतिक आयाम रचने के साथ ही अनुभवजन्य और प्रयोगसिद्ध प्रमाणों से भरे ज्ञान की उपयोगिता भी रखता है। इसमें उदाहरण और अनुभव भी शामिल हैं,जो हमारे पाठ्यक्रमों में आ रहे हैं। इसे केवल एक विषय के रूप में देखने की ग्रंथि से हमें मुक्त होना होगा।

भारतीय शिक्षा और विमर्श जगत की दूसरी समस्या यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध और संकलन के क्षेत्र में अभी कम काम हुआ है, जिसके कारण हमारे पास अध्ययन सामग्री का अभाव है। इस कमी को समझते हुए विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान अपने-अपने तरीके से इस दिशा में कार्यरत हैं। समाज विज्ञान से जुड़े शिक्षा संस्थानों में भारतीय समाज के ज्ञान,मेधा, तकनीकी पर शोध,संकलन और अध्ययन सामग्री बनाने का कार्य अभी पर्याप्त गुणात्मकता के साथ प्रारंभ हुआ है। अनेक विद्वान और समाजशास्त्री इस दिशा में कार्यरत हैं। इन शोधों का परिणाम शीघ्र ही दिखेगा। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान ने पाठ्यपुस्तक निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित पाठ्यपुस्तकें बनाने के अभियान को खासा महत्व दिया है। अन्य विश्वविद्यालयों को भी भारतीय ज्ञान परंपरा पर ज्ञान सृजन की परियोजना पर काम करना होगा। शिक्षा मंत्रालय में भारतीय ज्ञान परंपरा पर ज्ञान सृजन की प्रक्रिया को सहयोग देने के लिए एक उपखंड भी बनाया गया है,जो ऐसी परियोजनाओं को आर्थिक और दक्षता निर्माण में सहयोग करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनः खोज और उसे शोध एवं शिक्षण से जोड़ने की इस परियोजना की एक बड़ी समस्या इसके अर्थ का गलत पाठ और अनेक वृत्तांतात्मक उलझावों एवं अफवाहपूर्ण अवधारणाओं से गुजरना है। इस संदर्भ में पहली चुनौती इसके अर्थ एवं तत्व मीमांसा की है। भारतीय ज्ञान परंपरा वस्तुतः भारतीय समाज और उसके मिट्टी-पानी और सांस्कृतिक पर्यावरण में उपजा ज्ञान है। यह किसी एक जाति,पंथ और संस्कृति में सृजित एवं विकसित हुआ ज्ञान नहीं है,बल्कि यह उन सभी घटकों के सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव का ज्ञान समुच्चय है,जिनसे भारतीय समाज बनता है। यह बहुलतावादी सामाजिक संस्कृति से उभरा ज्ञान है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ता भारत

भारत के ऊर्जा भविष्य की नई तस्वीर

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़, नई दिल्ली

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

पृथ्वी पर ऊर्जा के परम्परागत साधन बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं,ऐसे में खतरा मंडरा रहा है कि यदि ऊर्जा के इन पारम्परिक स्रोतों का इसी प्रकार दोहन किया जाता रहा तो इन परम्परागत स्रोतों के समाप्त होने पर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यही कारण है कि पूरी दुनिया में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की जाने लगी और इसी कारण अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करने के प्रयास शुरू हुए। अक्षय का अर्थ है,जिसका कभी क्षय न हो अर्थात् अक्षय ऊर्जा वास्तव में ऊर्जा का असीम और अनंत विकल्प है और आज के समय में यह किसी भी राष्ट्र के अक्षय विकास का प्रमुख स्तंभ भी है। पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए ऐसी ऊर्जा तथा तकनीकें विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं,जिनसे ग्लोबल वार्मिंग की विकराल होती समस्या से दुनिया को कुछ राहत मिल सके। किसी भी राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए आज प्रदूषणरहित अक्षय ऊर्जा स्रोतों का समुचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता भी है। देश में अक्षय ऊर्जा के विकास और उपयोग को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए ही वर्ष 2004 से हर साल 20 अगस्त को 'अक्षय ऊर्जा दिवस' भी मनाया जाता है। आज न केवल भारत में बल्कि समूची दुनिया के समक्ष बिजली जैसी ऊर्जा की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं,साथ ही पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। चर्चित पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' के अनुसार इन गंभीर समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा ही एक ऐसा बेहतरीन विकल्प है,जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के साथ-साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में भी कारगर साबित होगी लेकिन अक्षय ऊर्जा की राह में भी कई चुनौतियां मुंह बाये सामने खड़ी हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन की देशभर में कई छोटी-छोटी इकाईयां हैं,जिन्हें एक ग्रिड में लाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इससे बिजली की गुणवत्ता प्रभावित होती है। भारत में अक्षय ऊर्जा के विविध स्रोतों का अपार भंडार मौजूद है लेकिन इनसे ऊर्जा उत्पादन करने वाले अधिकांश उपकरण विदेशों से आयात किए जाते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अनुसार,कुछ साल पहले सौर ऊर्जा के लिए करीब 90 प्रतिशत उपकरण विदेशों से आयात किए गए थे,जिससे बिजली उत्पादन की लागत काफी बढ़ गई। अब भी भारत की सौर सेल और मॉड्यूल की जरूरत का अधिकांश हिस्सा आयात से ही पूरा हो रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में एएलएमएम नियम और पीएलआई स्कीम के कारण यह निर्भरता घट रही है। 2023-24 में चीन से सौर सेल्स का 53 प्रतिशत और मॉड्यूल्स का 63 प्रतिशत भारत में आया।

देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में अब बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है,जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,बायो-पावर और छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अधिक बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से तथा परमाणु ऊर्जा से भी अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। कुल बिजली उत्पादन में अब अक्षय ऊर्जा का हिस्सा अब लगातार बढ़ रहा है, जो भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करता है। भारत में ऊर्जा खपत भी तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि वर्ष 2040 तक भारत में ऊर्जा की कुल मांग वर्तमान की तुलना में लगभग दोगुनी हो जाएगी। विशेषकर बिजली तथा ईंधन के रूप में उपभोग की जा रही ऊर्जा की मांग घरेलू एवं कृषि क्षेत्र के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी लगातार बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में ही बिजली तथा पैट्रोलियम जैसे ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोतों का लगभग 55 प्रतिशत उपभोग किया जाता है।

हम जिस बिजली से अपने घरों, दुकानों या दफ्तरों को रोशन करते हैं, जिस बिजली या पैट्रोलियम इत्यादि ऊर्जा के अन्य स्रोतों का इस्तेमाल कर खेती-बाड़ी या उद्योग-धंधों के जरिये देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया जाता है,क्या हमने कभी सोचा है कि वह बिजली या ऊर्जा के अन्य स्रोत हमें कितनी बड़ी कीमत पर हासिल होते हैं? यह कीमत न केवल आर्थिक रूप से बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी धरती पर विद्यमान हर प्राणी पर बहुत भारी पड़ती है। भारत में थर्मल पावर स्टेशनों में बिजली पैदा करने के लिए प्रतिदिन लगभग 18 लाख टन कोयले की खपत होती है। आज भी देश की लगभग 70 प्रतिशत से अधिक बिजली कोयले से ही पैदा होती है,शेष बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों,जल,गैस व परमाणु ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है।

दुनियाभर में ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 75 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन बिजली उत्पादन से ही होता है। यही कारण है कि अब सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, यदि अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाए तो वर्ष 2050 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 70 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है। भारत ने भी 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने और नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष 2070 तक प्राप्त करने का संकल्प लिया है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने से हमारी ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर कम होता जाएगा और इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

भारत में अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्मार्ट ग्रिड, बैटरी स्टोरेज और इलैक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे कदम भी तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जो अक्षय ऊर्जा को व्यावहारिक और टिकाऊ बनाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है,जिससे भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि निर्यातक देश भी बन सकेगा। सही मायने में अक्षय ऊर्जा ही आज भारत में विभिन्न रूपों में ऊर्जा की जरूरतों का प्रमुख विकल्प है,जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ टिकाऊ भी है। भारत धीरे-धीरे ही सही,अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज समय है कि हम आर्थिक बदहाली और भारी पर्यावरणीय विनाश की कीमत पर ताप, जल एवं परमाणु ऊर्जा जैसे पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय अपेक्षाकृत बेहद सस्ते और कार्बन रहित पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोतों के व्यापक स्तर पर विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ें। साथ ही हमें ऊर्जा की बचत की आदतें भी अपनानी होंगी क्योंकि ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग ही हमें सुरक्षित,समृद्ध और स्वच्छ भविष्य की ओर ले जाएगा।

एक देश,हजार दफ्तर और हर काम की एक कीमत

प्रो.आर.के.जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

भारत में रिश्वत अब जेब से निकलकर व्यवस्था की आदत बन चुकी है;कई बार सामान्य नागरिक का काम बिना इस 'अतिरिक्त कीमत' के आगे बढ़ता ही नहीं। थाने की मेज से तहसील की फाइल,आर टी ओ की खिड़की से पासपोर्ट कार्यालय तक–'कुछ करना पड़ेगा'जैसे वाक्यों ने भ्रष्टाचार को चुपचाप सामाजिक स्वीकृति दे दी है। इसी जड़ खामोशी को 2 जुलाई 2026 में दिल्ली के महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीटेक छात्र आर्यन निषाद ने डिजिटल चुनौती दी। उन्होंने ब्राइब्स डॉट एफवाईआई बनाया–एक मंच,जहां नागरिक पहचान छिपाकर रिश्वत की मांग दर्ज कर सकते हैं। विभाग,शहर,रकम और रिश्वत दी या ठुकराई–इतनी जानकारी से ही भ्रष्टाचार का नया नक्शा उभरने लगा।

इस पहल की असली धार उसकी सादगी में थी। न लंबी शिकायत प्रक्रिया,न दफ्तरों की दौड़,न पहचान उजागर करने की मजबूरी। नागरिक के

एक वेबसाइट,हजारों सवाल और भ्रष्टाचार का आईना एक युवा की पहल और व्यवस्था के सामने बड़ा सवाल

अनुभव को सीधे आंकड़े में ढाल दिया गया। शुरुआती रिपोर्टों में पुलिस विभाग सबसे आगे रहा;उसके बाद आरटीओ, राजस्व एवं भूमि रिकॉर्ड और पासपोर्ट कार्यालय सामने आए। 250 से अधिक शहरों से शिकायतें जुड़ीं और कई मामलों में मांगी गई रकम हजारों रुपये तक बताई गई। वेबसाइट ने स्पष्ट किया कि आंकड़े स्वैच्छिक रिपोर्टों पर आधारित हैं,पूरे भारत का वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं। फिर भी सीमित दायरे ने इसका महत्व कम नहीं किया। पहली बार लोगों की बिखरी पीड़ा एक साझा, सार्वजनिक डिजिटल तस्वीर में उभरने लगी।

सबसे चुभता संकेत शायद आंकड़ों के बीच छिपा वही सच था–कई लोगों ने रिश्वत देने से इनकार किया और फिर भी उनका काम हो गया। यह भ्रष्टाचार की उस पुरानी दलील पर सीधा सवाल है कि रिश्वत हर बार 'मजबूरी' होती है। जब बिना पैसे काम हो सकता है,तो फिर पैसे की मांग क्यों? ब्राइब्स डॉट एफवाईआई ने यही सवाल समाज के

सामने रख दिया। यहां भ्रष्टाचार अब धुंधली चर्चा नहीं,बल्कि रकम, विभाग और स्थान के साथ दर्ज अनुभव था। मानचित्र पर उभरते बिंदु महज शिकायतें नहीं थे; वे उस नागरिक आक्रोश के निशान थे,जिसे सरकारी फाइलें और मौखिक शिकायतें अक्सर निगल जाती हैं। किसी छोटे डिजिटल प्रयोग का इतनी तेजी से सार्वजनिक बहस बन जाना असाधारण था। कुछ ही घंटों में लाखों क्लिक और 50 लाख से अधिक (करीब 5 मिलियन) रिक्वेस्ट की खबरों ने ब्राइब्स डॉट एफवाईआई को राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया। सोशल मीडिया पर छात्रों, नागरिकों और तकनीक से जुड़े लोगों में चर्चा तेज हुई। एंजेल इन्वेस्टर डॉ. अनिरुद्ध मालपानी की ₹30,000 की मदद ने इसके आगे बढ़ने की संभावना दिखाई। लेकिन लोकप्रियता के साथ दुरुपयोग, शिकायतों की विश्वसनीयता,कानूनी सुरक्षा और वित्तीय ढांचे के सवाल उठे। वेबसाइट स्वेच्छा से ऑफलाइन कर दी गई। टीम ने इसे सावधानी का कदम बताया। बाद में अनिश्चितकालीन ब्रेक की घोषणा करते हुए डेटा स्थायी रूप से डिलीट करने और वेबसाइट हमेशा के लिए बंद करने की बात कही गई; फिर भी डेटा और कानूनी ढांचे पर सवाल बने रहे।

ब्राइब्स डॉट एफवाईआई की असली कहानी कोड से आगे,लोकतंत्र की उस जमीन पर शुरू होती है जहां नागरिक और व्यवस्था आमने-सामने होते हैं। वेबसाइट बनाना आसान है,लेकिन उसे सुरक्षित,भरोसेमंद और लंबे समय तक जनहित में चलाना कठिन। भारत में सरकारी शिकायत तंत्र मौजूद हैं, फिर भी कई नागरिक वहां जाने से कतराते हैं–डर रहता है कि काम न अटके, अधिकारी नाराज न हो या शिकायतकर्ता की पहचान मुसीबत न बन जाए। गुमनाम रिपोर्टिंग ने इसी डर में एक दरार खोली। मगर वायरल होने के बाद मंच संभालना कठिन हो गया। इससे स्पष्ट है–तकनीक अकेले भ्रष्टाचार की जड़ नहीं काट सकती; उसे कानूनी संरक्षण, सख्त मॉडरेशन, विश्वसनीय सत्यापन और संस्थागत सहयोग चाहिए।

अब प्रश्न यह नहीं कि ब्राइब्स डॉट एफवाईआई कितनी शिकायतें बटोर सकता था; असली प्रश्न है–उनका अंजाम क्या होता? यदि किसी विभाग, शहर या कार्यालय से बार-बार रिश्वत की शिकायतें मिलें, तो क्या निगरानी तंत्र हरकत में आना चाहिए? क्या ऐसे आंकड़े भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसियों के लिए शुरुआती चेतावनी बन सकते हैं? नागरिक जोखिम लेकर सूचना दे और व्यवस्था उसे महज डिजिटल शोर मानकर टाल दे,तो शिकायत मंच का मकसद अधूरा रहेगा। आर्यन निषाद ने एआई की मदद से कोड लिखा और मनीष सहानी जैसे सहयोगियों के साथ एक सरल विचार को सार्वजनिक प्रयोग में बदल दिया। अब असली कसौटी उस व्यवस्था की है,जिसे इस आईने में अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा है।

इस प्रयोग की सबसे उम्मीदभरी तस्वीर युवा भारत की बेचैनी में दिखती है। नई पीढ़ी भ्रष्टाचार पर सिर्फ बहस नहीं, उसके खिलाफ औजार बनाना चाहती है। कोई ऐप बना सकता है, कोई डेटा सहेज सकता है, कोई मानचित्र बना सकता है और कोई सोशल मीडिया से सवाल लाखों तक पहुंचा सकता है। यदि ब्राइब्स डॉट एफवाईआई मजबूत कानूनी आधार,विश्वसनीय सत्यापन और जिम्मेदार डेटा-सुरक्षा के साथ लौटता है, तो यह नागरिक भागीदारी की मिसाल बन सकता है। और अगर नहीं लौटता,तब भी उसका असर नहीं मिटेगा। उसने भरोसा जगाया है कि शिकायत दर्ज की जा सकती है, पहचान छिपाकर सच सामने लाया जा सकता है और निजी अनुभव को सामूहिक सूचना में बदला जा सकता है।

ब्राइब्स डॉट एफवाईआई को भ्रष्टाचार के खिलाफ'अंतिम हथियार'कहना जल्दबाजी होगी,लेकिन इसे जरूरी चेतावनी समझना चाहिए। वेबसाइट बंद हो सकती है,सर्वर थम सकते हैं और वायरल चर्चा मिट सकती है;पर नागरिक अनुभव को दबाना अब आसान नहीं। भ्रष्टाचार की मजबूत ढाल कानून से ज्यादा हमारी सामूहिक चुप्पी रही है। जिस दिन रिश्वत मांगने वाले को डर होगा कि उसका कृत्य दर्ज हो सकता है,उसी दिन जोखिम का समीकरण बदलेगा। आर्यन निषाद ने कोई चमत्कारी इलाज नहीं दिया;उन्होंने व्यवस्था के सामने आईना रख दिया। अब फैसला नागरिकों और संस्थाओं का है–आईने में दिखती दरारें भरी जाएंगी या आईना ही हटा दिया जाएगा।

आधुनिक युग का अन्नदाता...

संजय एम तराणेकर
इन्दौर
मध्यप्रदेश

वो दरवाज़े पर जब घंटी बजती,
चेहरे पर मुस्कान लिए आता है।
मौसम धूप हो चाहे तेज़ बारिश,
वह अपना फर्ज़ खूब निभाता है।

उसके कभी हाथ में खाना होता,
तो कभी दवा हैं या कभी सामान।
हमारी छोटी-छोटी सी जरूरत को,
देता है वह सभी को अपना मान।

उसके मोबाइल की घंटी बजते ही,
रास्ते पर फटाफट निकल पड़ता है।
शहर की हर गली से परिचित होता,
जैसे सबकी उम्मीद बनके चलता है।

मन-सपन

गरिमा राकेश गौत्तम,राजस्थान

सपने नयन नही
सपने मन देखता
क्योंकि यदि नयन
सपने देखते तो
आज लुई ब्रेल की
ब्रेल लिपि ना होती
हेलेन केलर जैसी
महिला न होती
ना सूरदास के पद
होते
ना रवीन्द्र जैन का
संगीत होता
स्टीव वंडर के गाने न होते
तो नयनों का काम
सृष्टि को देखना है
सपने तो मन दिखाता हैं
वो मन जो देह में
स्तिथ न होकर भी
देह को अपने वश में रखता है
और वो मन ही पल पल
नये नये सपने सजाता है

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

रेडियो : बदलते माध्यमों के बीच बची रही इंसानी आवाज

रेडियो : मनोरंजन से जनजागरण तक एक जीवित विरासत

माँ की लोरी से 'मन की बात' तक–रेडियो की यात्रा

कृति आर.के.जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

कुछ आवाजें कानों तक पहुँचकर ठहरती नहीं, भीतर अपना घर बना लेती हैं। रेडियो भी ऐसी ही आवाज है। राष्ट्रीय रेडियो दिवस पर उसकी स्मृति किसी बीते उपकरण की नहीं,बल्कि उस अदृश्य हमसफर की याद है, जिसने गीतों में आनंद, सूचनाओं में भरोसा और खामोशी में साथ दिया। बिनाका गीतमाला की मखमली धुनों से 'मन की बात' की आत्मीयता तक,रेडियो की यात्रा केवल तकनीक के बदलते रूपों की कहानी नहीं है। कभी वह गाँव की चौपाल पर गूँजा,कभी रात के सन्नाटे में अकेले कमरे का सहारा बना और आज मोबाइल व इंटरनेट से फिर कानों तक पहुँच रहा है। साधन और समय बदलते रहे, आवाज का अपनापन आज भी जस का तस है।

शाम ढलते ही ट्रांजिस्टर की आवाज उठती, घरों की दीवारें छोटी और दूरियाँ मिटने लगती थीं। अमीन सायानी की आवाज में गीत गूँजता तो पूरा मोहल्ला एक भाव में बंध जाता। रेडियो के पास तस्वीर नहीं थी,फिर भी वह मन में अनगिनत दृश्य रच देता था। क्रिकेट की कमेंट्री में श्रोता गेंद की रफ्तार, स्टेडियम की हलचल और चौके की गूँज तक महसूस करता था। यही रेडियो का सम्मोहन था–दिखाए बिना दिखा देना। उसने श्रोता को केवल सुनने वाला नहीं,कल्पना का सह-रचनाकार बना दिया। आज पॉडकास्ट और इंटरनेट रेडियो उसी जादू को नए रूप में आगे बढ़ा रहे हैं; आवाज और मंच बदले हैं, दिल तक पहुँचने का रास्ता नहीं।

रेडियो की ताकत आवाज में नहीं,उस भरोसे में थी जो करोड़ों दिलों तक पहुँचाता था। स्वतंत्रता संग्राम में जब अखबार सेंसर की कैंची से जूझ रहे थे,तब आजाद हिंद रेडियो की आवाजें भारतीयों तक पहुँचती थीं। वे केवल समाचार नहीं,स्वतंत्रता की बेचैनी और उम्मीद थीं। आजादी के बाद रेडियो ने नवजात राष्ट्र को साझा सार्वजनिक जीवन दिया। किसानों को मौसम व खेती की जानकारी, माताओं को स्वास्थ्य-संदेश, बच्चों को कहानियाँ और बुजुर्गों को भक्ति-संगीत में सांत्वना मिली। आपदा में इसका महत्व उभरा–सुनामी हो या उत्तराखंड की बाढ़,जब संचार ठप्प पड़ते हैं,बैटरी वाला रेडियो राहत, चेतावनी और उम्मीद का सहारा बनता है। संयुक्त राष्ट्र भी आपदा-संचार में इसकी विश्वसनीयता रेखांकित करता है।

टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल की चमक ने रेडियो को पीछे धकेला,फिर भी उसकी आवाज खत्म नहीं हुई। 'मन की बात' ने उसे फिर करोड़ों घरों के संवाद में ला खड़ा किया। खासियत यह रही कि यह महज सरकारी घोषणा नहीं लगी; संबोधन में ऐसा अपनापन था,मानो कोई आँगन में बैठकर पूछ रहा हो–क्या हाल है तुम्हारा? स्वच्छ भारत,बेटी बचाओ,डिजिटल इंडिया जैसे विषय हों या किसी नागरिक की प्रेरक कहानी, सहज भाषा ने बात को नारा नहीं,संवाद बना दिया। रेडियो की ताकत आदेश में नहीं,बातचीत में है,क्योंकि वही आवाज जोड़ती है,जिसमें उपदेश कम और अपनापन अधिक हो।

जब स्क्रीनें हमारी आँखों को बाँध रही हैं,रेडियो कानों के रास्ते हमें भीतर के मनुष्य से मिला सकता है। सामुदायिक रेडियो गाँव-गाँव स्थानीय बोलियों में बोलते हैं,इसलिए उनकी विश्वसनीयता अलग है। वे किसानों को बाजार भाव, महिलाओं को स्वास्थ्य जानकारी और युवाओं को कौशल व रोजगार की दिशा देते हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए रेडियो कभी-कभी घर का पता बन जाता है। हजारों मील दूर बैठा व्यक्ति मातृभाषा का गीत सुनता है तो लगता है,जैसे अपनी गली के मोड़ पर लौट आया हो। वैश्वीकरण का यही कोमल रूप है–दुनिया बड़ी हो,पर आवाज में अपनी मिट्टी की खुशबू बची रहे।

रेडियो ने आवाजों के साथ अनगिनत सपनों को भी पहचान दी। उसने रेडियो जॉकी,ध्वनि कलाकार,उद्घोषक और स्क्रिप्ट राइटर जैसे कामों के दरवाजे खोले। खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए, जिनके पास मंच कम थे, आवाज ही पहचान बन गई। यहाँ चेहरा जरूरी नहीं था;शब्द,उच्चारण,संवेदना और संवाद की क्षमता ही पूँजी थी। यह लैंगिक समानता की कोई ऊँची घोषणा नहीं,बल्कि रोजमर्रा के प्रसारण में चली शांत क्रांति थी। डिजिटल इंडिया के दौर में भी रेडियो ग्रामीण भारत का शिक्षक,साथी और सांस्कृतिक वाहक है। वह स्क्रीन के बिना शिक्षा, स्वास्थ्य,कृषि,संगीत और लोक-संस्कृति घर-घर पहुँचा सकता है।

समय ने रेडियो को कई बार पीछे छूटा हुआ समझा, लेकिन हर तकनीकी बदलाव के साथ उसने खुद को नए रूप में सामने रखा। ट्रांजिस्टर से एफएम, एफएम से इंटरनेट स्ट्रीमिंग और फिर पॉडकास्ट तक उसने हर बदलाव को अपने पक्ष में मोड़ा। उसकी ताकत किसी उपकरण में नहीं, इंसान की सुनने की जरूरत में है। स्क्रीन लगातार हमें दिखाती है,जबकि रेडियो हमें ठहरकर सुनना सिखाता है। जब हर व्यक्ति बोलना चाहता है,तब ऐसा माध्यम भी जरूरी है जो बिना चेहरे के साथ दे,बिना शोर के सूचना दे और बिना दृश्य तमाशे के कल्पना को जीवित रखे। इसी अर्थ में रेडियो तकनीक से अधिक एक सामाजिक आदत और सांस्कृतिक स्मृति है।

रेडियो को बीते दिनों की धुंध में रख देना उसकी असली पहचान को छोटा करना होगा। राष्ट्रीय रेडियो दिवस पर कभी फोन की रोशनी बुझाकर किसी आवाज को बिना स्क्रीन के सुनिए; संभव है उसमें माँ की लोरी लौट आए, बचपन का गीत सुनाई दे,पुराने क्रिकेट की उत्तेजना जाग उठे या बस यह भरोसा मिले कि आप अकेले नहीं हैं। बिनाका गीतमाला से पॉडकास्ट तक,मनोरंजन से 'मन की बात' तक रेडियो की यात्रा जारी है। वह हर बार अपना रूप बदलता है, स्वभाव नहीं। जब तक मनुष्य में कहानी सुनने की इच्छा,दूर की आवाज से जुड़ने की आकांक्षा और सुनने वाले कान हैं,तब तक रेडियो हवा में रहेगा। वह मशीन नहीं, संगी है–और संगी की जरूरत कभी खत्म नहीं होती।

बिना फर्नीचर पहुंचाए 67 लाख का भुगतान कमीशन के खेल में 15 साल बाद दो गिरफ्तार

2.70 करोड़ की खरीदी में सामने आई गड़बड़ी,बिल फर्म ने लगाए और कमीशन की रकम अफसर तक पहुंचाने का आरोप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए फर्नीचर खरीदने के नाम पर 15 साल पहले हुआ खेल अब खुलकर सामने आया है। जिस फर्नीचर की स्कूलों में आपूर्ति ही नहीं हुई, उसके बिल लगाकर सरकारी खजाने से भुगतान करा दिया गया। जांच में अकेले एक फर्म से जुड़े भुगतान में शासन को 67 लाख 15 हजार 814 रुपए की आर्थिक क्षति सामने आई है। मामले में पुलिस ने तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक सत्यप्रकाश पाण्डेय और फर्म संचालक संजय पटेल को गिरफ्तार किया है। मामला वर्ष 2010-11 का है। उस समय अविभाजित सरगुजा जिले के सूरजपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज क्षेत्र की पूर्व माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर खरीदी के लिए राजीव गांधी शिक्षा मिशन, अंबिकापुर को करीब 2.70 करोड़ रुपए का आवंटन मिला था। खरीदी के लिए पंजीकृत फर्मों को सीएसआईडीसी की निर्धारित दरों पर आपूर्ति के आदेश जारी किए गए थे। विवेचना में मेसर्स दर्शन फेब्रिकेशन के संचालक संजय पटेल की भूमिका सामने आई। पुलिस के अनुसार फर्म ने वास्तविक रूप से फर्नीचर की आपूर्ति नहीं की,लेकिन कागजों में आपूर्ति दर्शाते हुए बिल प्रस्तुत कर दिए गए। इन्हीं बिलों के आधार पर शासकीय राशि का भुगतान भी करा लिया गया। इस तरह बिना सामान पहुंचाए सरकारी राशि निकालने का मामला सामने आया।

भुगतान का हिस्सा कमीशन में बंटने का आरोप

जांच में पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिलने का दावा है, जिनके मुताबिक फर्म को मिले भुगतान में से संजय पटेल ने अपना कमीशन रखने के बाद शेष राशि तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक सत्यप्रकाश पाण्डेय को दी। पुलिस ने इसे दोनों के बीच मिलीभगत और षड्यंत्र के जरिए शासकीय राशि के दुरुपयोग का मामला माना है।

15 साल तक चलता रहा मामला, 2017 में दर्ज हुई एफआईआर

इस मामले में वर्ष 2017 में अपराध क्रमांक 28/2017 दर्ज किया गया था। करीब 15 साल पुराने मामले में लंबी जांच के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 19 अगस्त 2026 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में पेश करने के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

अब दूसरे सप्लायर भी जांच के घेरे में

जांच यहीं खत्म नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार फर्नीचर आपूर्ति करने वाले अन्य सप्लायरों की भूमिका में भी अनियमितता के तथ्य मिले हैं। तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अन्य सप्लायरों से भी कमीशन लिए जाने की जानकारी सामने आई है। अब पुलिस वास्तविक आपूर्ति,भुगतान और कथित कमीशन की रकम की जांच कर रही है।

इन धाराओं में कार्रवाई

आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी), 13(2) तथा आईपीसी की धारा 120-बी, 420 और 409 के तहत कार्रवाई की गई है। प्रकरण की अग्रिम विवेचना जारी है।

प्रेमी के साथ पत्नी को देख भडक़ा पति...फावड़े से दोनों की हत्या

मैनपाट में दोहरे हत्याकांड से सनसनी,रिश्तेदार के घर के कमरे में मिले दोनों के खून से सने शव,आरोपी पति फरार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

मैनपाट के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के बिसरपानी गांव में मंगलवार रात पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख पति ने फावड़े से हमला कर दोनों की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। बुधवार सुबह रिश्तेदार के घर में दोनों के खून से सने शव मिलने के बाद घटना की जानकारी पुलिस को हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। जानकारी के अनुसार बिसरपानी दारापारा निवासी बाबूलाल मझवार (35) मंगलवार शाम खेत गया था। इसी दौरान उसकी पत्नी नईहारो मझवार (32) गांव में ही रिश्तेदार सोमारू मझवार के घर चली गई। वहां उसका कथित प्रेमी बेंजे बड़ा (35) भी पहुंच गया। दोनों घर के बगल में बने कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। खेत से लौटने के बाद बाबूलाल पत्नी को घर में नहीं देखकर उसकी तलाश करने लगा। वह सोमारू के घर पहुंचा, जहां पत्नी और बेंजे बड़ा कमरे में मिले। पुलिस के अनुसार दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद बाबूलाल का दोनों से विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते तीनों

के बीच मारपीट होने लगी। विवाद बढऩे पर घर का मालिक सोमारू वहां से भाग गया। इसी दौरान बाबूलाल ने फावड़े से पत्नी नईहारो और बेंजे बड़ा पर हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से दोनों की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

सुबह घर पहुंचा तो मिलीं दोनों की लाशें : बुधवार सुबह सोमारू अपने घर पहुंचा तो कमरे में दोनों की खून से सनी लाशें पड़ी थीं। दोनों के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। सूचना मिलने पर कमलेश्वरपुर थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज प्रजापति पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है।

एनएसयूआई उपाध्यक्ष ज्ञान तिवारी के नेतृत्व में कुलसचिव को सौंपा गया ज्ञापन

छात्रों और ग्रामीणों की समस्याओं पर हुई चर्चा...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय (सरगुजा विश्वविद्यालय),अंबिकापुर में छात्रों की शैक्षणिक-प्रशासनिक समस्याओं और आसपास के ग्रामीणों के जमीन संबंधी मुद्दों को लेकर एनएसयूआई विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष ज्ञान तिवारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कुलसचिव से मुलाकात की। इस दौरान छात्र नेताओं और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से कुलसचिव से चर्चा कर अपनी मांगों व समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को आ रही विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक परेशानियों से कुलसचिव को अवगत कराया। साथ ही, परिसर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों द्वारा उठाई गई जमीन संबंधी समस्याओं व अन्य स्थानीय मुद्दों पर भी गंभीरता से ध्यान देने और जल्द से जल्द समाधान निकालने की मांग की गई। इस दौरान एनएसयूआई उपाध्यक्ष ज्ञान तिवारी के साथ छात्र नेता अभिनव काशी,आकाश पटेल,आनंद साहू,पवन सोनी,कान्हा पटेल एवं अन्य सहयोगी उपस्थित रहे। उनके साथ विश्वविद्यालय क्षेत्र व आसपास के गांववासी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कुलसचिव ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समस्याओं के उचित निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक सूचनाओं, निर्देशों और आगामी ज्ञापनों के लिए छात्र व नागरिक संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

गांधीनगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

महिला संबंधी अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए थाना गांधीनगर पुलिस टीम ने दुष्कर्म के एक मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया और बाद में शादी करने से साफ इंकार कर दिया।

10 साल से कर रहा था शोषण

थाना गांधीनगर से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2016 से लेकर 15 अगस्त 2026 के मध्य उसके जान-पहचान के एक युवक ने उसे शादी का प्रलोभन देकर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी की पहचान अभिषेक कुमार यादव (31 वर्ष), निवासी बड़सरा (भैयाथान, जिला सूरजपुर), हाल मुकाम गांधीनगर बिजली ऑफिस गली के रूप में हुई है। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी ने साफ मना कर दिया।

बीएनएस और एसटी/एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज

प्रार्थिया की लिखित शिकायत पर थाना गांधीनगर में आरोपी अभिषेक यादव के खिलाफ अपराध क्रमांक 516/26, धारा 69 (बीएनएस) व एसटी/एससी एक्ट की धारा 3(2)1 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।

पूछताछ में कबूला जुर्म,भेजा गया जेल

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने लगातार दबिश देकर आरोपी अभिषेक यादव को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अपराध साबित होने पर पुलिस ने आरोपी अभिषेक यादव आत्मज रामनारायण यादव को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में भेज दिया गया है। इस पूरी त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर उप निरीक्षक दिलीप दुबे,प्रशिक्षु उप निरीक्षक भारतीय मार्कण्डेय,सहायक उप निरीक्षक सुभाष ठाकुर,महिला आरक्षक सरस्वती,आरक्षक राहुल सिंह और आरक्षक रमन मण्डल की सराहनीय व सक्रिय भूमिका रही।

साइबर जागृति अभियान के अंतर्गत छात्र एवं छात्राओं को किया गया जागरूक

साईं बाबा स्कूल अंबिकापुर,लटोरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनपुर,मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल रघुनाथपुर,धौरपुर बस स्टैंड, थाना सीतापुर के ग्राम वंदना,स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल गांधीनगर के छात्र एवं छात्राएं रहें उपस्थित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

डीआईजी/एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी साइबर सेल श्री रितेश चौधरी के कुशल नेतृत्व में जिला अंतर्गत प्रथम सप्ताह सभी स्कूल-कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में 'साइबर जागृति अभियान' आयोजित किया जा रहा है! साइबर अपराधों के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ाने तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित साइबर जागृति अभियान के अंतर्गत आज साईं बाबा स्कूल अंबिकापुर, लटोरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनपुर, मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल रघुनाथपुर, धौरपुर बस स्टैंड,थाना सीतापुर के ग्राम वंदना, स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल गांधीनगर में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र एवं छात्राओं एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम

के दौरान छात्र छात्राओं एवं नागरिकों को वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों एवं ऑनलाइन ठगी के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी गई। विशेष रूप से OTP, UPI एवं QR Code फ्रॉड,फर्जी लिंक, APK फाइल,फर्जी कस्टमर केयर नंबर, सोशल मीडिया फ्रॉड,फर्जी प्रोफाइल, अनजान वीडियो कॉल,सेक्सटॉर्शन एवं डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से समझाया गया। छात्र छात्राओं एवं नागरिकों को बताया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, PIN, CVV, पासवर्ड अथवा बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने, अनजान APK फाइल डाउनलोड करने तथा किसी के कहने पर क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें। साथ ही सोशल मीडिया पर निजी फोटो, वीडियो एवं व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई। साइबर अपराध होने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई के महत्व को समझाते हुए छात्राओं को राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा cybercrime.gov.in के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

उन्हें बताया गया कि साइबर ठगी का शिकार होने पर बिना देरी किए शिकायत दर्ज कराने से ठगी गई राशि को रोकने की संभावना बढ़ जाती है। कार्यक्रम के दौरान 'जागरूकता की एक Selfie' अभियान के अंतर्गत छात्राओं को जागरूकता QR Code के संबंध में जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं एवं नागरिकों को QR Code के माध्यम से साइबर जागरूकता अभियान से जुड़ने तथा साइबर सुरक्षा से संबंधित संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान के प्रति जागरूकता एवं सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से छात्र छात्राओं एवं नागरिकों द्वारा QR Code के साथ Selfie भी ली गई। उपरोक्त कार्यक्रम में स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल के प्राचार्य डॉ राजकुमार यादव, स्कूल के शिक्षक शिक्षिका, साईं बाबा स्कूल की प्राचार्य श्रीमती प्राची गोयल, नवा बिहान से श्री मंगल पाण्डेय, उप निरीक्षक अभय तिवारी, सहायक उप निरीक्षक परशुराम पैकरा,महिला थाना से सहायक उप निरीक्षक गंभीर साय,महिला आरक्षक सविता मरावी महिला आरक्षक संगीता, आरक्षक राहुल केरकेट्टा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं पुलिस मितान एवं साइबर वॉलंटियर टीम से अतुल गुप्ता, विक्की गुप्ता एवं राजकुमार ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए छात्राओं को साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कीं।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल की छत से टपक रहा पानी, टीवी वार्ड में गिरा प्लास्टर

बाल-बाल बचे मरीज और स्टाफ,जर्जर भवन में बारिश के बीच इलाज कराने मजबूर मरीज,हर साल मरम्मत पर खर्च के बाद भी नहीं सुधरी स्थिति

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

पिछले तीन दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। अस्पताल की छत और दीवारों से पानी टपक रहा है। सबसे खराब स्थिति टीवी वार्ड की है,जहां छत से लगातार पानी टपकने के दौरान अचानक प्लास्टर का एक हिस्सा नीचे गिर गया। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई मरीज या स्टाफ नर्स नहीं आया। प्लास्टर गिरने से वार्ड में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। टीवी वार्ड में कई जगहों से पानी टपक रहा है। इससे भर्ती मरीजों के बेड के आसपास पानी जमा हो रहा है। मरीजों को इसी परेशानी के बीच इलाज कराना पड़ रहा है। लगातार पानी टपकने से अस्पताल प्रबंधन के सामने भी वार्ड की व्यवस्था संभालने की चुनौती बनी हुई है।

अन्य वार्डों में भी टपक रहा पानी : मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भवन काफी पुराना है और कई हिस्सों में छत व दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है। अस्पताल के विभिन्न वार्डों सहित अन्य हिस्सों में भी छत और दीवारों से पानी टपकने की शिकायत सामने आती है। इससे मरीजों के साथ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

हर साल मरम्मत,फिर भी समस्या बरकरार : बारिश के दौरान अस्पताल की छत से पानी टपकने की समस्या इस साल की नहीं है। हर वर्ष बारिश शुरू होते ही अस्पताल के कई हिस्सों में पानी रिसने लगता है। अस्पताल की मरम्मत के नाम पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों को जर्जर भवन में बारिश के बीच इलाज कराने की मजबूरी बनी हुई है।

ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में सडक़

बिजली और स्मार्ट मीटर पर चर्चा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अंबिकापुर की दूसरी बैठक बुधवार को राजीव भवन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंदरजीत सिंह धंजल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ब्लॉक कांग्रेस प्रभारी अरविंद सिंह गप्पू सहित मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में पार्टी का सदस्यता अभियान चलाकर नए सदस्यों को जोडऩे के साथ शहर की बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और सडक़ समस्याओं पर चर्चा हुई। सडक़ समस्या को लेकर एनएच और नगर निगम का घेराव तथा स्मार्ट मीटर के विरोध में बिजली कार्यालय का घेराव करने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया। मतदाता सूची का अवलोकन कर त्रुटियों में सुधार कराने पर भी चर्चा हुई। आगामी कार्यक्रमों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी से चर्चा करने की बात कही

गई। बैठक में धनमीत सिंह छाबड़ा, अमित वर्मा, तीरथ चौधरी, मिराज रंगरेज, बालेश्वर तिर्की, शंकर प्रजापति सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

दो माह में हुआ जर्जर...

विधायक मद से बना पुलिया

-संवाददाता-
लखनपुर,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिनिया में विधायक मद से करीब 10 लाख रुपये की लागत से बनाई गई पुलिया निर्माण के महज दो महीने बाद ही जर्जर हो गई है। इससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। गांव वालों का आरोप है कि पुलिया का निर्माण बेहद घटिया तरीके से कराया गया और इंजीनियरिंग मानकों को ताक पर रखकर ऐसी जगह पर बनाया गया, जहां इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं थी। लखनपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के बिनिया गांव में एक नाले के ऊपर पुलिया निर्माण शुरू होते ही लोगों ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि एक तो निर्माण घटिया तरीके से हो रहा है और दूसरा गलत जगह पर पुलिया बनवाया जा रहा है, क्योंकि जिस

स्थान पर पुलिया बनाई गई,वहां सड़क ही नहीं है। गांव वालों का आरोप है कि जिस स्थान के लिए पुलिया स्वीकृत हुई थी, वहां निर्माण न कर दूसरे स्थल पर बना दिया गया। अब स्थिति यह है कि पुलिया का बेस ही बह गया है। पानी पुलिया के अंदर से गुजरने के बजाय नींव के नीचे से दूसरी तरफ बह रहा है। इस मामले में ग्रामीण यांत्रिक विभाग के एसडीओ प्रवीण खलखो ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि एप्रोच विंग वाल की लंबाई कम बनाई गई है और काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। बरसात के बाद काम करवाया जाएगा।

टीएस सिंहदेव ने होलीक्रॉस स्कूल में छात्रों से किया सीधा संवाद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

एनएसयूआई के छात्र संवाद कार्यक्रम के तहत पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बुधवार को होलीक्रॉस स्कूल के सभाकक्ष में छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने जेन-जी के जंतर-मंतर आंदोलन, छत्तीसगढ़ में शिक्षा-स्वास्थ्य व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं और अंबिकापुर की सडक़ों से जुड़े सवाल पूछे। छात्रों ने सिंहदेव से उनकी निजी रुचियों को लेकर भी सवाल किए। सरगुजा एनएसयूआई ने जेन-जी और जेन-अल्फा के विचारों और उनकी मांगों को समझने तथा उनका प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से यह संवाद श्रृंखला शुरू की है। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम पूरी तरह गैरराजनीतिक रखा गया है। इसकी पहली कड़ी में 30 जुलाई को सिंहदेव ने माउंट लिटेरा स्कूल के विद्यार्थियों से संवाद किया था। छात्रों ने जेन-जी के जंतर-मंतर आंदोलन को लेकर भी सिंहदेव से सवाल किया। उन्होंने कहा कि जेन-जी और जेन-अल्फा का अपनी मांगों को लेकर सडक़ पर उतरना तकलीफदेह है। सरकार को युवाओं की समस्याओं को समझने के लिए उनसे सार्थक संवाद करना चाहिए और उनकी जायज मांगों को

पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए। सिंहदेव ने कहा कि अच्छी शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी हासिल करना नहीं है,बल्कि विद्यार्थियों को भविष्य का अच्छा नागरिक बनाना भी है। छात्रों ने सिंहदेव से उनकी साहित्यिक रुचियों और ऑस्ट्रेलिया में स्काईडाइविंग के अनुभव को लेकर भी सवाल पूछे। साहित्य पढऩे के सवाल पर उन्होंने बताया कि उन्हें हल्के दार्शनिक विषयों वाला लेखन पसंद है। वे स्वामी विवेकानंद से संबंधित साहित्य का गहराई से अध्ययन करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण आम लोगों से नियमित संवाद में दिनचर्या का अधिकांश समय चला जाता है, इसलिए साहित्य पढऩे के लिए सीमित समय मिलता है। सूचनाओं के लिए वे आजकल

यू-ट्यूब का भी अधिक उपयोग करते हैं। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आशीष जायसवाल ने बताया कि छात्र संवाद की यह श्रृंखला स्कूलों के साथ महाविद्यालयों में भी आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में होलीक्रॉस स्कूल प्रबंधन के अलावा सतीश बारी, अंकित जायसवाल, ऋषिकेश मिश्रा और धीरज गुप्ता मौजूद रहे।

CMYK

'इलाज' करने वाले डॉक्टरों के चुनाव का इलाज कौन करेगा?

आयुर्वेद परिषद में डाक मतपत्र से सरकारी प्रभाव तक घमासान

आयुर्वेद परिषद चुनाव में 'शासकीय बनाम गैर-सरकारी' की जंग! डाक मतपत्र,दबाव और प्रशासनिक प्रभाव के आरोपों से घिरी निर्वाचन प्रक्रिया

डाक मतपत्र से लेकर सरकारी दबाव तक सवालों की कतार,रजिस्ट्रार का पत्र आया तो मानो चुनावी व्यवस्था को भी याद आया कि मतदाता स्वतंत्र होता है!

आयुर्वेद परिषद चुनाव: वोट डॉक्टर देंगे या 'प्रभावशाली व्यवस्था' तय करेगी?

डाक मतपत्र से दबाव तक...आयुर्वेद परिषद चुनाव पर उठे सवाल,मंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद भी विवाद कायम

आयुर्वेद परिषद चुनाव में घमासान : डाक मतपत्र,सरकारी प्रभाव और दबाव के आरोपों ने बढ़ाई बेचैनी

'सरकारी प्रभाव' के साये में आयुर्वेद परिषद चुनाव! डाक मतपत्र से लेकर मतदाताओं पर दबाव तक उठे सवाल

आयुर्वेद परिषद चुनाव पर संकट के बादल: शिकायत,जांच के निर्देश और बहिष्कार तक पहुंचा विवाद

मतपत्र किसके हाथ,वोट किसके प्रभाव में? आयुर्वेद परिषद चुनाव की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल

-न्यूज डेस्क-

अंबिकापुर,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

चुनाव लोकतंत्र का वह उत्सव है,जिसमें मतदाता की उंगली पर स्याही लगती है और व्यवस्था की परीक्षा होती है,लेकिन छत्तीसगढ़ आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति तथा प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के चुनाव में मामला कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। यहां सवाल यह नहीं रह गया कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिलेंगे, बल्कि सवाल यह खड़ा हो गया है कि वोट वास्तव में मतदाता के हाथ तक पहुंच भी रहा है या रास्ते में ही किसी 'व्यवस्था' के हाथ लग जा रहा है? आमतौर पर चुनाव में ईवीएम को लेकर बहस होती है, बूथ की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं और मतगणना पर नजर रहती है, लेकिन इस चुनाव ने लोकतांत्रिक प्रयोग को एक नया अध्याय दे दिया है–डाक मतपत्र का अध्याय, मतपत्र डाक से निकला,रास्ते में गया और फिर किसके हाथ पहुंचा,इस सवाल ने कई प्रत्याशियों को इतना परेशान कर दिया कि अब चुनाव से ज्यादा उन्हें चुनाव की व्यवस्था समझने में रुचि हो रही है,सरगुजा संभाग के प्रत्याशी डॉ. भुवन भास्कर साहू सहित कई प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर शिकायतें की गई हैं,शिकायतों में मतदाताओं पर कथित दबाव,शासकीय पद के प्रभाव के इस्तेमाल,डाक मतपत्रों को एकत्र करने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसे आरोप लगाए गए हैं,इन आरोपों की सत्यता अभी जांच का विषय है, लेकिन सवाल इतने गंभीर हैं कि उन्हें महज चुनावी हार-जीत की खीझ कहकर किनारे करना आसान नहीं होगा।

सरकारी डॉक्टरों का प्रभाव : सेवा नियम और चुनावी नियम आमने-सामने?–विवाद का दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा गंभीर है,कुछ प्रत्याशियों का आरोप है कि शासकीय संस्थानों में पदस्थ कुछ अधिकारी और चिकित्सक अपने पद एवं प्रभाव का इस्तेमाल कर मतदाताओं को किसी विशेष प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावित कर रहे हैं,आरोपों में तबादले, सीआर खराब होने अथवा प्रशासनिक कार्रवाई का भय दिखाए जाने जैसी बातें भी सामने आई हैं, यदि यह आरोप गलत हैं तो जांच में साफ हो जाएंगे। लेकिन यदि सही हैं तो सवाल केवल चुनाव का नहीं,बल्कि सरकारी पद की मर्यादा का भी है, क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब यह तो नहीं हो सकता कि कार्यालय में फाइल के साथ मतदाता की पसंद भी घूमे। अधिकारी का पद प्रशासन चलाने के लिए होता है, किसी प्रत्याशी की चुनावी रणनीति चलाने के लिए नहीं, यही वजह है कि शिकायतकर्ताओं की नजर में यह चुनाव अब 'शासकीय बनाम गैर-सरकारी' चिकित्सकों की लड़ाई जैसा रूप लेता जा रहा है।

रजिस्ट्रार का पत्र: आखिर चुनावी व्यवस्था को यह बात बतानी क्यों पड़ी?

सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब 13 अगस्त 2026 को निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रार डॉ. संजय शुक्ला की ओर से शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों के प्राचार्यों, अधीक्षकों और जिला आयुष अधिकारियों को पत्र जारी किए जाने की जानकारी सामने आई, पत्र में शासकीय संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं चिकित्सकों द्वारा मतदाताओं पर दबाव डालकर मतपत्र एकत्र किए जाने की शिकायतों का उल्लेख किया गया, भय, दबाव अथवा प्रलोभन से मतपत्र एकत्र करने को निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाला कृत्य बताया गया, अब सवाल यह है कि यदि सब कुछ सामान्य था तो ऐसा पत्र जारी करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और यदि शिकायतें इतनी गंभीर थीं कि रजिस्ट्रार कार्यालय को शासकीय संस्थानों को बाकायदा आगाह करना पड़ा, तो क्या केवल पत्र जारी कर देने से मामला खत्म हो जाएगा? यह कुछ ऐसा ही है जैसे सड़क पर ट्रैफिक जाम देखकर बोर्ड लगा दिया जाए–'जाम न लगाएं।' सवाल यह है कि जाम लगाने वाले पर कार्रवाई कौन करेगा?

मंत्री कार्यालय भी पहुंची शिकायत, अब फाइल की चाल पर नजर

मामला केवल रजिस्ट्रार कार्यालय तक नहीं रुका। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कार्यालय ने भी शिकायत का संज्ञान लिया,11 अगस्त 2026 के पत्र में संचालक, आयुष को मतपत्र वितरण,प्रशासनिक पद के कथित दुरुपयोग और मतदाताओं पर अनुचित दबाव जैसे आरोपों की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाने की जानकारी सामने आई है,अब यहां लोकतंत्र का अगला अध्याय शुरू होता है, शिकायत से जांच, जांच से रिपोर्ट और रिपोर्ट से कार्रवाई, लेकिन असली सवाल यह है कि यह प्रक्रिया कितनी तेज होगी? कहीं ऐसा न हो कि चुनाव पहले पूरा हो जाए और जांच बाद में उस फाइल को खोजती रह जाए जिसमें जांच की जांच लिखी हो,प्रत्याशियों की चिंता यही है कि जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही हो, तब शिकायतों का समाधान भी चुनाव की समयसीमा के भीतर होना चाहिए।

'मतपत्र संग्रह अभियान' कौन चला रहा था?–शिकायतों में एक और गंभीर आरोप यह है कि कुछ स्थानों पर डाक मतपत्रों को एकत्र किए जाने की कोशिश हुई, यदि मतदाता स्वयं अपना मतपत्र भरकर भेजता है तो यह उसकी स्वतंत्र चुनावी प्रक्रिया है,लेकिन यदि कोई व्यक्ति कई मतदाताओं के मतपत्र इकट्ठा करने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति आखिर चुनाव लड़ रहा है या डाकघर की वैकल्पिक शाखा चला रहा है? यहां भी निष्कर्ष निकालने से पहले जांच जरूरी है, लेकिन यदि ऐसे दस्तावेज या प्रमाण उपलब्ध हैं तो निर्वाचन अधिकारी के लिए उनकी जांच करना अनिवार्य हो जाता है।

प्रत्याशियों ने कहा...पहले चुनाव करवाइए, फिर परिणाम गिनिए...

विवाद इतना बढ़ा कि विभिन्न संभागों के कई प्रत्याशियों ने संयुक्त ज्ञापन देकर वर्तमान चुनाव को नियमावली के प्रावधानों के तहत अमान्य अथवा शून्य घोषित करने तथा स्वतंत्र प्रशासनिक अधिकारी की निगरानी में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है,13 अगस्त 2026 के संयुक्त ज्ञापन में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर,सरगुजा और कवर्धा संभाग से जुड़े प्रत्याशियों के हस्ताक्षर होने की जानकारी सामने आई है,डॉ. शिव नारायण द्विवेदी,डॉ. सोमेश कुशवाहा,डॉ. सत्य संस्कार बले,डॉ. योगेश कुमार शर्मा,डॉ. आलोक कुमार,डॉ. शिशिरकांत शुक्ला,डॉ. आशीष पाल,डॉ. भुवन भास्कर साहू और डॉ. रुखसार खान सहित अन्य प्रत्याशियों की ओर से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं, यहां मामला किसी एक प्रत्याशी की शिकायत नहीं रह जाता, जब अलग-अलग संभागों से आवाजें उठने लगें तो व्यवस्था को कम से कम इतना तो पूछना ही चाहिए कि धुआं आखिर किस तरफ से उठ रहा है?

डाक मतपत्र है या 'घूमता हुआ गोपनीय पैकेट'?

शिकायत के साथ सामने आए दस्तावेजों ने सबसे बड़ा सवाल डाक मतपत्रों की डिलीवरी को लेकर खड़ा किया है, मतपत्र वाले लिफाफे पर साफ तौर पर 'गोपनीय' और 'पंजीकृत डाक' लिखा है,यानी इसे सामान्य चिट्ठी समझकर किसी के भी हाथ में पकड़ा देने का मामला नहीं होना चाहिए। लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में अलग-अलग मतदाताओं के लिए भेजे गए मतपत्रों की प्राप्ति को लेकर एक जैसे हस्ताक्षरों पर सवाल उठाया गया है, अब लोकतंत्र का गणित बड़ा सरल है–एक मतदाता, एक मतपत्र, लेकिन अगर कई मतदाताओं के मतपत्र एक ही व्यक्ति के हाथ में पहुंच गए हों, तो फिर गणित थोड़ा कठिन हो जाता है,सवाल है की मतपत्र किसने लिया? क्या वह अधिकृत व्यक्ति था? क्या डाक विभाग ने पहचान सत्यापित की? क्या संबंधित चिकित्सकों ने स्वयं अपने मतपत्र प्राप्त किए? और यदि किसी अन्य व्यक्ति ने मतपत्र लिए तो उसकी अनुमति किसने दी? इन सवालों का जवाब किसी राजनीतिक बयान से नहीं, बल्कि डाक विभाग के मूल रिकॉर्ड, डिलीवरी रजिस्टर,हस्ताक्षर और संबंधित मतदाताओं के बयान से मिलेगा, यानी इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण 'गवाह' कोई नेता नहीं,बल्कि डाक वितरण रजिस्टर बन गया है।

आरोप सही या गलत-जांच के बिना फैसला संभव नहीं...

इस पूरी कहानी में सबसे जरूरी सावधानी यही है कि शिकायत और आरोप को दोष सिद्धि नहीं माना जा सकता,संभव है कि डाक वितरण में कोई तकनीकी या प्रक्रियागत गलती हुई हो, यह भी संभव है कि कुछ आरोप चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण लगाए गए हों, इसलिए किसी अधिकारी,कर्मचारी या प्रत्याशी को बिना जांच दोषी ठहराना उचित नहीं होगा,लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है,जब दस्तावेज सामने हों,मंत्री कार्यालय संज्ञान ले चुका हो और रजिस्ट्रार कार्यालय स्वयं दबाव एवं मतपत्र संग्रह की शिकायतों को लेकर पत्र जारी कर चुका हो, तब जांच को टालना भी सवाल पैदा करेगा।

अब सात सवाल,जिनसे भाग नहीं सकती व्यवस्था, पूरे विवाद का सार...सात सवालों में समेटा जा सकता है...

- पहला, अलग-अलग मतदाताओं के मतपत्र किसने प्राप्त किए?
- दूसरा,क्या सभी मतपत्र संबंधित चिकित्सकों तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचे?
- तीसरा,डाक विभाग ने प्राप्तकर्ता की पहचान किस आधार पर सुनिश्चित की?
- चौथा,क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी ने मतदाताओं पर दबाव बनाया?
- पांचवां,क्या किसी व्यक्ति ने कई मतपत्र एकत्र किए?
- छठा,शिकायत मिलने के बाद संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित किए गए या नहीं?
- सातवां,क्या जांच पूरी होने तक चुनाव परिणाम अथवा विवादित मतपत्रों के संबंध में कोई विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी?

इन सवालों का जवाब मिल गया तो आधा विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा।

चुनाव की असली जीत किसकी होगी?–आयुर्वेद परिषद चुनाव में जीत किसी डॉक्टर,किसी समूह या किसी खेमे की हो सकती है, लेकिन असली जीत तब होगी जब चुनाव के बाद कोई मतदाता यह न कहे कि उसका वोट उसके हाथ से पहले किसी और के हाथ में पहुंच गया था, लोकतंत्र में मतपत्र की कीमत कागज की कीमत से नहीं, मतदाता के अधिकार से तय होती है,इसलिए एक मतपत्र भी यदि संदिग्ध तरीके से वितरित हुआ है तो उसकी जांच जरूरी है,फिलहाल परिषद चुनाव की कहानी कुछ ऐसी हो गई है–उम्मीदवार मैदान में हैं,मतदाता परेशान हैं,डाक विभाग के रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो गए हैं,रजिस्ट्रार पत्र लिख रहे हैं और मंत्री कार्यालय जांच के निर्देश दे चुका है,अब जरूरत है कि फाइलों की रफ्तार भी मतपत्रों जितनी तेज हो,क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वह नहीं होती जब कोई हार जाता है,सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब हारने वाला यह मानने लगे कि उसका वोट उससे पहले ही कहीं और तय हो चुका था,इसलिए इस चुनाव में अब सवाल केवल यह नहीं कि कौन जीतेगा? बड़ा सवाल यह है–क्या चुनाव भी जीतेगा?

ड्रंक एंड ड्राइव पर भारी जुर्माना : बाइक और ई-रिक्शा चालक पर लगा 20,000 रुपये का अर्थदंड

यातायात शाखा द्वारा मामले में वाहन चालकों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्यवाही की जा रही है,इसी क्रम में यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग मोटरसायकल क्रमांक सीजी /15/डीबी /0613 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम अमरदीप लकड़ा आत्मज याक़ूब लकड़ा उम्र 35 वर्ष साकिन सीतापुर थाना सीतापुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, दूसरे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान ई रिक्शा क्रमांक सीजी /15/डी वाय/1512 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम सैफ खान आत्मज लाल मोहम्मद उम्र 34 वर्ष साकिन दर्रीपारा थाना अंबिकापुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, ई रिक्शा चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया। मोटरसायकल एवं ई रिक्शा चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरण में वाहन चालकों को 10000/- रुपये प्रत्येक के अर्थदंड कुल 20000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं। सम्पूर्ण कार्यवाही में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त, एवं अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।

वाराणसी अस्सी घाट से पवित्र गंगाजल लेकर निकले कांवड़िए पहुंचे छत्तीसगढ़ बॉर्डर...

वाराणसी अस्सी घाट से 419 किमी की 'महायात्रा 360' पहुंची छत्तीसगढ़ बॉर्डर,विधायक रामकुमार टोप्पो की अगुवाई में उमड़ा जनसैलाब....

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

धार्मिक आस्था और अटूट विश्वास की सबसे लंबी कांवड़ यात्राओं में से एक 'महायात्रा 360' आज छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पहुंच गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस पावन यात्रा की शुरुआत बीते 13 अगस्त को वाराणसी के प्रसिद्ध अस्सी घाट से पवित्र गंगाजल उठाकर की गई थी। लगभग 419 किलोमीटर की इस कठिन और लंबी पैदल यात्रा को तय करने के बाद सभी कांवड़िए छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं।

मैनपाट के स्वयंभू चोरकीपानी धाम में होगा जलाभिषेक : यह भव्य महायात्रा कुल 419 किलोमीटर का सफर तय कर मैनपाट ब्लॉक में स्थित स्वयंभू विराजमान शिवलिंग 'चोरकीपानी मंदिर' पहुंचेगी। सावन मास के आखिरी सोमवार को चोरकीपानी धाम में बाबा भोलेनाथ का पवित्र गंगाजल से जलाभिषेक किया जाएगा। इसके पश्चात वहां विशाल हवन, पूजन और भव्य भंडारे के साथ इस पावन यात्रा का समापन होगा। इस वर्ष इस महायात्रा का यह लगातार पांचवा वर्ष है।

विधायक बनने से पहले से टोप्पो कर रहे हैं अगुवाई

आपको बता दें कि सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रामकुमार टोप्पो के नेतृत्व में यह यात्रा प्रतिवर्ष बेहद श्रद्धाभाव के साथ पूर्ण होती है। खास बात यह है कि श्री रामकुमार टोप्पो जब विधायक नहीं बने थे,यह यात्रा तब से अनवरत रूप से आयोजित की जा रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस यात्रा पर बाबा काशी विश्वनाथ, मां गंगे और चोरकीपानी बाबा की असीम कृपा बरस रही है।

विधानसभा की सुख-समृद्धि के लिए मेरा हर एक कदम : विधायक टोप्पो

छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पहुंचने के बाद माननीय विधायक श्री रामकुमार टोप्पो ने क्षेत्रवासियों के नाम अपना भक्तिमय संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि...'वाराणसी अस्सी घाट से हमारे सीतापुर विधानसभा में विराजमान चोरकीपानी मंदिर की दूरी लगभग 5 लाख कदम की है। मेरा हर एक कदम हमारी सीतापुर विधानसभा के प्रत्येक नागरिक की सुख, समृद्धि और निरंतर उन्नति के लिए उठ रहा है। मैं बाबा भोलेनाथ से यही कामना करता हूं कि जनता ने मुझे जो दायित्व सौंपा है, मैं उसे पूरी निष्ठा के साथ हरसंभव पूरा कर सकूं। '

बलरामपुर में फसल चरने से नाराज दबंगों ने गाय पर टांगी और लाठियों से किया हमला

गाय की कमर की हड्डी टूटी..पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे

-संवाददाता-

बलरामपुर,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

रा.गंज जिले के विजयनगर चौकी क्षेत्र में पशु क्रूरता का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। खेत में फसल नुकसान पहुंचाने से नाराज चार आरोपियों ने एक राय होकर एक बेजुबान गाय पर लाठी-डंडों और टांगी (कुल्हाड़ी) से जानलेवा हमला कर दिया। इस बर्बर हमले में गाय की कमर की हड्डी टूट गई और वह मौके पर ही खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार, विजयनगर पुलिस को घटना की सूचना मिलते पर तत्काल चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। शुरुआती जांच में सामने आया कि बेजुबान गाय गलती से खेत में घुसकर फसल चर रही थी। इससे आक्रोशित होकर आरोपियों ने गाय को घेर लिया और उस पर धारदार टांगी व लाठियों से हमला कर दिया। हमले में अत्यधिक खून बहने और कमर टूटने के कारण गाय चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ हो गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नेसार अंसारी पिता स्वर्गीय मुसई अंसारी ताज मलिक पिता इरशाद उर्फ बूटी अंसारी चेरकू अंसारी उर्फ दिलशान अंसारी पिता स्वर्गीय जुम्मन अंसारी उर्फ शेखावत नन्हका अंसारी उर्फ राज मालिक पिता बूटी अंसारी उर्फ इरशाद अंसारी सभी निवासी चौकी विजयनगर थाना रामानुजगंज गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 142/2026 के तहत बीएनएस की धारा 325, छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4 व 10, और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(क) के तहत आरोपियों गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।

CMYK

पुल टूटा, रपटा बहा और अब सवालों की बाढ़!

14 महीने बाद भी स्थायी पुल अधूरा, 15 लाख का रपटा भी 15 दिन में बहा

30 जून 2025 : ध्वस्त हुआ मुख्य पुल

18 जुलाई 2026 : बहा वैकल्पिक रपटा

स्थायी पुल बनेगा कब? इंतजार कब तक?

पहले पुल बहा,फिर रपटा बहा...अब बहस में कौन बचेगा-जनता या जिम्मेदारी?

पुल कागजों में,रपटा नदी में...जनता फिर सड़क की तलाश में!

50 से ज्यादा खबरों के बाद भी पुल अधूरा,रपटा भी बहा...जनता का सवाल-अब कब बनेगा रास्ता?

स्थायी पुल की फाइल चलती रही, रपटा तीन दिन की बारिश में चल बसा!

वीडियो में राजनीति,नदी में बहा रपटा... लेकिन ग्रामीणों का सवाल अब भी कायम...पुल कब बनेगा?

भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता दीप नारायण साहू ने ग्रामीणों की परेशानी और 15 लाख के रपटा की गुणवत्ता पर उठाए सवाल

मंत्री समर्थकों ने वीडियो जारी कर बताया...स्थायी पुल बजट में शामिल, प्रक्रिया जारी,लेकिन 14 महीने बाद भी जमीन पर निर्माण शुरू नहीं...

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

गोबरी नदी पर 30 जून 2025 को ध्वस्त हुए पुल का मामला अब केवल एक टूटे हुए पुल या बह चुके वैकल्पिक रपटा तक सीमित नहीं रह गया है,करीब 14 महीने से ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित है, स्थायी पुल का निर्माण अभी जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा और जिस वैकल्पिक व्यवस्था के भरोसे बरसात में ग्रामीणों को राहत देने की कोशिश की गई थी,करीब 15 लाख रुपये की लागत वाला वह रपटा भी तेज बारिश में क्षतिग्रस्त होकर बह गया,अब इस पूरे मामले में राजनीति के दो रंग सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। एक ओर इसी क्षेत्र के निवासी और भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता बताए जा रहे दीप नारायण साहू ने टूटे हुए रपटा पुल पर खड़े होकर वीडियो जारी किया और स्थानीय ग्रामीणों की परेशानी सामने रखी, दूसरी ओर उनके वीडियो के बाद मंत्री समर्थकों की ओर से एक जवाबी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि स्थायी पुल के निर्माण को इस वर्ष के बजट में शामिल किया जा चुका है और शासन स्तर पर अंतिम स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है,दिलचस्प बात यह है कि दोनों पक्षों के वीडियो सामने आने के बाद भी मूल सवाल जस का तस खड़ा है–30 जून 2025 को मुख्य पुल टूटने के बाद 14 महीने में स्थायी पुल निर्माण की प्रक्रिया आखिर किस चरण तक पहुंची और ग्रामीणों को स्थायी राहत कब मिलेगी?

दीप नारायण साहू ने सवाल उठाया, मंत्री पर व्यक्तिगत आरोप नहीं...

दीप नारायण साहू ने अपने वीडियो में जिस तरह से अपनी बात रखी,उसमें उन्होंने क्षेत्रीय समस्या को प्रमुखता दी,उन्होंने कहा कि वह भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और इसी क्षेत्र के निवासी भी हैं,जिस मार्ग से ग्रामीण रोजाना आवागमन करते हैं,उसी मार्ग की समस्या को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है, वीडियो में साहू ने बताया कि उन्होंने इस समस्या का उल्लेख मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के सामने भी किया था,उनके अनुसार उन्होंने मंत्री से तीन बार इस विषय में चर्चा की, लेकिन उन्हें कोई सार्थक जवाब या कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली,इसके बाद उन्होंने टूटे हुए रपटा स्थल पर पहुंचकर अपनी बात वीडियो के माध्यम से रखी,उनका मुख्य सवाल 15 लाख रुपये की लागत से बने रपटा की निर्माण तकनीक को लेकर था, उन्होंने आशंका जताई कि जिस स्थान पर पानी का बहाव अधिक था,वहां पर्याप्त संख्या में ह्यूम पाइप नहीं लगाए गए,उनका कहना था कि यदि अतिरिक्त ह्यूम पाइप लगाए जाते और नीचे की ओर पर्याप्त गहराई में पानी निकासी की व्यवस्था की जाती तो संभवतः रपटा ज्यादा समय तक टिक सकता था, हालांकि इन तकनीकी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी आवश्यक है,रपटा टूटने के वास्तविक कारणों का निर्धारण तकनीकी जांच से ही हो सकता है।

14 महीने में बजट तक पहुंचा मामला,अब आगे कितना इंतजार? 30 जून 2025 को पुल टूटने के बाद ग्रामीणों ने एक वर्ष से अधिक समय तक परेशानी झेली,दैनिक घटती-घटना ने भी इस मुद्दे को लगातार उठाया और पिछले एक वर्ष में इस मामले पर 50 से अधिक खबरें और फॉलोअप प्रकाशित किए,इन खबरों में पुल टूटने से लेकर वैकल्पिक रपटा,उसकी एप्रोच रोड,डब्ल्यूएमएम कार्य,निर्माण गुणवत्ता और बरसात में रपटा की परीक्षा तक लगातार सवाल उठाए गए,अब रपटा भी बह चुका है, ऐसे में ग्रामीणों के लिए यह जानना जरूरी है कि स्थायी पुल का काम कब शुरू होगा,यदि 14 महीने में मामला अभी बजट और स्वीकृति की प्रक्रिया में है, तो आगे निविदा और निर्माण में कितना समय लगेगा? क्या अगली बरसात से पहले पुल तैयार हो जाएगा? यदि नहीं,तो अगले बरसात के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था कौन करेगा?

'प्राकृतिक' कह देने से सवाल खत्म नहीं होते–रपटा तेज बारिश में बह गया,मंत्री समर्थकों के वीडियो में इसे भारी बारिश और तेज बहाव से जोड़कर प्राकृतिक घटना बताया गया, लेकिन यहां भी एक तकनीकी सवाल बचा रहता है,यदि यह क्षेत्र हर वर्ष बरसात में तेज जलप्रवाह से प्रभावित होता है और विभाग को पहले से पता था कि नदी में पानी का बहाव बढ़ सकता है,तो अस्थायी रपटा किस अधिकतम जलप्रवाह को सहने के लिए डिजाइन किया गया था? यदि वह केवल सामान्य बारिश के लिए था, तो क्या ग्रामीणों को यह जानकारी दी गई थी? और यदि उद्देश्य ही यह था कि स्थायी पुल बनने तक ग्रामीणों का आवागमन बरसात में बाधित न हो,तो वैकल्पिक व्यवस्था को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पर्याप्त मजबूत बनाना किसकी जिम्मेदारी थी? इन सवालों का जवाब किसी राजनीतिक वीडियो से नहीं, बल्कि स्वीकृत ड्राइंग,तकनीकी डिजाइन,लागत अनुमान, ह्यूम पाइप की संख्या,निरीक्षण रिपोर्ट और निर्माण गुणवत्ता की जांच से मिलेगा।

सवाल विभाग से...क्या नदी के बहाव का सही आकलन हुआ था?

दीप नारायण साहू के वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि उन्होंने सवाल केवल जनप्रतिनिधि से नहीं, बल्कि निर्माण विभाग से भी किया, उनका कहना था कि नदी के बहाव को देखते हुए निर्माण में पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए थी, यहीं से मामला तकनीकी जांच की मांग तक पहुंचता है, यदि रपटा का डिजाइन सामान्य जलप्रवाह को ध्यान में रखकर बनाया गया था, तो क्या उसमें असामान्य या तेज बारिश के दौरान आने वाले पानी का आकलन किया गया था? यदि किया गया था तो कितनी क्षमता के जलप्रवाह के लिए डिजाइन तैयार किया गया था? कितने ह्यूम पाइप स्वीकृत थे और वास्तव में कितने लगाए गए? क्या निर्माण के बाद तकनीकी निरीक्षण हुआ था? इन सवालों का जवाब दस्तावेजों और स्थल निरीक्षण से ही सामने आ सकता है।

जवाबी वीडियो में मंत्री समर्थकों ने कहा...'बड़े प्रोजेक्ट में समय लगता है'

दीप नारायण साहू के वीडियो के बाद मंत्री समर्थकों की ओर से सोशल मीडिया पर एक दूसरा वीडियो सामने आया, इस वीडियो में कहा गया कि बिना पूरी सच्चाई जाने आरोप लगाना आसान है, वीडियो में बताया गया कि ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए तत्काल राहत देने के लिए करीब 15 लाख रुपये की लागत से अस्थायी रपटा बनाया गया था, जवाबी वीडियो में यह भी कहा गया कि भारी बारिश और तेज बहाव के कारण अस्थायी ढांचा टूट गया और इसे प्राकृतिक स्थिति बताया गया, इसके साथ ही वीडियो में यह दावा किया गया कि गंगोटी से सूरजपुर मार्ग पर गोबरी नदी में स्थायी पुल निर्माण को इस वर्ष के बजट में शामिल किया जा चुका है और मंत्री शासन से अंतिम स्वीकृति के लिए प्रयासरत हैं, यह दावा यदि संबंधित सरकारी दस्तावेजों से पुष्ट होता है तो निश्चित रूप से स्थायी समाधान की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक चरण माना जाएगा,लेकिन यहीं दूसरा बड़ा सवाल भी पैदा होता है की बजट में शामिल होना और पुल का जमीन पर बन जाना एक ही बात नहीं है, बजट प्रावधान के बाद प्रशासकीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, निविदा, ठेका प्रक्रिया, कार्यादेश और वास्तविक निर्माण जैसे कई चरण होते हैं, इसलिए ग्रामीणों के लिए असली सवाल यह है कि इन प्रक्रियाओं में अभी कौन-सा चरण पूरा हुआ है और निर्माण स्थल पर काम कब शुरू होगा?

एक वीडियो में सवाल,दूसरे वीडियो में जवाब...लेकिन ग्रामीणों का सवाल फिर भी बाकी...

पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दीप नारायण साहू ने अपने वीडियो में मंत्री को अपमानित या व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने के बजाय अपनी परेशानी और विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए,उन्होंने स्वयं को भाजपा कार्यकर्ता बताते हुए यह भी कहा कि यदि जनता अपने जनप्रतिनिधि से अपनी समस्या नहीं कहेगी तो किससे कहेगी,इसके बावजूद उनके वीडियो के जवाब में मंत्री समर्थकों का वीडियो सामने आया,यहीं से राजनीतिक बहस शुरू हो गई, लेकिन लोकतंत्र में किसी जनप्रतिनिधि के क्षेत्र का व्यक्ति,चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक हो,अपने क्षेत्र की समस्या पर सवाल उठाता है तो उसका जवाब तथ्यों के साथ दिया जाना चाहिए,इसी तरह यदि किसी आरोप में तथ्यात्मक त्रुटि है तो उसका खंडन दस्तावेजों के साथ होना चाहिए,व्यक्तिगत या राजनीतिक बहस से ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं होगा।

मंत्री का बचाव करने से ज्यादा जरूरी है काम की स्थिति बताना

मंत्री समर्थकों के जवाबी वीडियो में यदि यह बताया गया है कि स्थायी पुल बजट में शामिल है,तो यह महत्वपूर्ण जानकारी है,लेकिन इससे अगला सवाल और मजबूत होता है लो अब तक क्या हुआ और आगे कब होगा? यदि अंतिम स्वीकृति बाकी है तो वह कब तक मिलेगी? निविदा कब जारी होगी? कार्यादेश कब होगा? निर्माण कब शुरू होगा? पुल कब तक पूरा होगा? और तब तक ग्रामीण किस रास्ते से सुरक्षित आवागमन करेंगे? इन सवालों के जवाब सार्वजनिक किए जाने चाहिए, क्योंकि ग्रामीणों को यह जानने में दिलचस्पी नहीं है कि सोशल मीडिया पर कौन किसके समर्थन में वीडियो बना रहा है, उनकी चिंता यह है कि उन्हें रोज अपने घर, खेत,स्कूल,अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए सुरक्षित रास्ता कब मिलेगा।

स्थायी पुल बनने तक वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी

यह भी समझना होगा कि स्थायी पुल बनने में समय लग सकता है,बड़े पुल का निर्माण तत्काल संभव नहीं होता,लेकिन जब तक स्थायी पुल नहीं बनता,तब तक वैकल्पिक मार्ग ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि बरसात में ग्रामीणों का संपर्क दोबारा न टूटे,पहले मुख्य पुल टूटा,एक वर्ष बाद वैकल्पिक रपटा बनाया गया,रपटा कुछ ही समय बाद तेज बारिश में बह गया,अब स्थिति फिर वहीं पहुंच गई जहां से कहानी शुरू हुई थी,अर्थात न स्थायी पुल तैयार है,न वैकल्पिक व्यवस्था सुरक्षित बची है।

दैनिक घटती-घटना के सवालों की भी हुई पुष्टि?

दैनिक घटती-घटना ने रपटा बनने के बाद ही उसकी मजबूती और बरसात में क्षमता को लेकर सवाल उठाए थे,7 जुलाई 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट में यह सवाल प्रमुखता से उठाया गया था कि पहली बरसात इस रपटा की वास्तविक परीक्षा होगी, कुछ ही समय बाद रपटा क्षतिग्रस्त हो गया,इससे अखबार द्वारा उठाए गए सवालों की प्रासंगिकता और बढ़ गई है,हालांकि निर्माण में तकनीकी खामी थी या रपटा असाधारण जलप्रवाह की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ,इसका अंतिम निष्कर्ष विशेषज्ञ जांच के बाद ही निकलेगा।

अब राजनीति नहीं, समयबद्ध कार्रवाई चाहिए...

इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के वीडियो सामने आ चुके हैं,एक पक्ष ने समस्या बताई,दूसरे पक्ष ने सरकार और मंत्री के प्रयास बताए,लेकिन ग्रामीणों की समस्या अभी भी वहीं है,इसलिए अब सबसे जरूरी है कि सरकार और संबंधित विभाग सार्वजनिक रूप से यह बताए कि स्थायी पुल निर्माण की फाइल किस स्तर पर है और उसकी समयसीमा क्या है,यदि बजट में प्रावधान हो चुका है तो उसकी प्रति सार्वजनिक की जा सकती है,यदि प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है तो आदेश जारी किया जा सकता है। यदि निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो उसकी जानकारी दी जा सकती है, और यदि अभी इनमें से कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो ग्रामीणों को वास्तविक स्थिति बताई जानी चाहिए।

अंतिम सवाल...पुल कब बनेगा?

गोबरी नदी का पुल 30 जून 2025 को टूटा था,इसके बाद एक वर्ष से अधिक समय बीत गया,स्थायी समाधान अभी भी प्रक्रिया में है,वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बनाया गया करीब 15 लाख रुपये का रपटा भी बारिश में बह गया,अब सवाल किसी व्यक्ति के वीडियो का नहीं है,सवाल किसी मंत्री के समर्थन या विरोध का भी नहीं है,सवाल उन ग्रामीणों का है जिनका रास्ता टूटा है, सवाल उस बच्चे का है जिसे स्कूल पहुंचना है,सवाल उस मरीज का है जिसे अस्पताल जाना है,सवाल उस किसान का है जिसे अपनी उपज बाजार तक ले जानी है,सवाल उस परिवार का है जिसे रोज इसी रास्ते से गुजरना है,और सबसे बड़ा सवाल यही है,जब 30 जून 2025 को पुल टूट गया था,तो अगस्त 2026 तक भी स्थायी पुल जमीन पर क्यों नहीं आया? बजट में शामिल होना राहत की शुरुआत हो सकती है,लेकिन ग्रामीणों के लिए राहत का अंत तभी होगा जब मजबूत स्थायी पुल बनकर तैयार होगा और उस पर सुरक्षित आवागमन शुरू होगा,तब तक सोशल मीडिया के वीडियो चाहे जितने बनें,सवाल वहीं रहेगा 'पुल कब बनेगा और तब तक जनता जाएगी कैसे?'

CMYK

हसदेव के उद्गम मेण्ड्रा में गूंजा 'हर-हर महादेव', नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत व सांसद ज्योत्स्ना महंत ने हसदेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक

सांसद ज्योत्स्ना महंत ने अपने हाथों से बाटा भंडारे का प्रसाद...

राजन पाण्डेय

कोरिया/सोनहत,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

हसदेव नदी के पावन उद्गम स्थल मेण्ड्रा स्थित प्रसिद्ध हसदेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को आस्था,भक्ति और जनविश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिला। पवित्र सावन माह के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत एवं कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्स्ना महंत सूरज महंत पूर्व विधायक गुलाब कमरो के साथ मेण्ड्रा पहुंचे और भगवान हसदेश्वर महादेव की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर परिसर 'बम-बम भोले','हर-हर महादेव' और भगवान शिव के जयकारों से गुंजायमान रहा,महंत दंपत्ति ने भगवान भोलेनाथ के समक्ष प्रदेशवासियों,क्षेत्र के लोगों एवं किसानों के सुख-समृद्धि, खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न विशेष पूजा-अर्चना ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया,मंदिर के पुजारी पंडित अनित दुबे एवं प्रेमसागर तिवारी ने विधिवत पूजा एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया।

सांसद ज्योत्स्ना महंत ने स्वयं बांटा प्रसाद,श्रद्धालुओं से हुआ आत्मीय संवाद- पूजा-अर्चना के बाद सांसद ज्योत्स्ना महंत ने स्वयं श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया,इस दौरान उनका ग्रामीणों और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के साथ आत्मीय संवाद भी हुआ, सांसद को अपने बीच पाकर ग्रामीणों में खासा उत्साह दिखाई दिया,प्रसाद वितरण के दौरान कई बुजुर्गों एवं महिलाओं ने सांसद से बातचीत की और अपनी भावनाएं साझा कीं। ज्योत्स्ना महंत ने भी सहजता और आत्मीयता के साथ लोगों से मुलाकात की,मंदिर परिसर का यह दृश्य धार्मिक आयोजन के साथ-साथ जनप्रतिनिधि और आमजन के बीच बने आत्मीय संबंधों का भी प्रतीक बना।

दिग्गज नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रही मौजूदगी- कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि,कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रमुख रूप से पूर्व विधायक गुलाब कमरो, पूर्व विधायक अंबिका सिंह देव,जिला कांग्रेस अध्यक्ष (एमसीबी) अशोक श्रीवास्तव, राजकुमार केशरवानी,योगेश शुक्ला,लालमुनि यादव, ज्योत्स्ना राजवाड़े,अविनाश पाठक, प्रकाश चंद्र साहू,सुरेश सिंह,बाल करण सोनपाकर,कृष्ण कुमार राजवाड़े,संतोष यादव एवं राजबहादुर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी,जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हसदेव उद्गम की धरती पर उमड़ा आस्था का सैलाब

हसदेव नदी के उद्गम स्थल मेण्ड्रा का धार्मिक एवं प्राकृतिक महत्व लंबे समय से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है,यहां स्थित हसदेश्वर महादेव मंदिर में सावन के दौरान दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचते हैं,महंत दंपत्ति के आगमन की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण,श्रद्धालु,कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मंदिर परिसर में जुटे, पूजा के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जयघोष किया। पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आया,महंत दंपत्ति ने श्रद्धालुओं के साथ पूजा में सहभागिता की और भगवान शिव से क्षेत्र की उन्नति एवं जनकल्याण की प्रार्थना की।

ग्रामीणों से सीधा संवाद,समस्याओं पर हुई चर्चा

धार्मिक अनुष्ठान के पश्चात सांसद ज्योत्स्ना महंत ने क्षेत्र के ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने सड़क,बिजली,पानी,आवागमन,शिक्षा, स्वास्थ्य सहित क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न आवश्यकताओं और मांगों से उन्हें अवगत कराया,महंत दंपत्ति ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विषयों पर अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कई स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया,जिससे ग्रामीणों में संतोष दिखाई दिया। सांसद महंत ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाना और उनके समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है।

धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश

हसदेव नदी का उद्गम स्थल होने के कारण मेण्ड्रा का महत्व धार्मिक आस्था के साथ-साथ पर्यावरणीय दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है,हसदेव अंचल की पहचान जल,जंगल और प्राकृतिक संपदा से जुड़ी हुई है,ऐसे में हसदेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम ने क्षेत्र की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया,श्रद्धालुओं ने हसदेव नदी के उद्गम स्थल की पवित्रता एवं प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने का संकल्प लेने की आवश्यकता पर भी जोर दिया,लोगों का कहना था कि धार्मिक आस्था के इन प्रमुख केंद्रों के साथ-साथ जलस्रोतों और आसपास के प्राकृतिक क्षेत्र का संरक्षण भी सामूहिक जिम्मेदारी है।

भक्ति,जनविश्वास और प्रकृति का अनूठा संगम

मेण्ड्रा में हसदेश्वर महादेव के दरबार में आयोजित यह धार्मिक आयोजन केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं रहा। हसदेव के उद्गम की पावन धरती पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गूंजते शिव जयकारे,महंत दंपत्ति का ग्रामीणों से संवाद और प्रसाद वितरण ने पूरे आयोजन को जनआस्था एवं आत्मीयता से भर दिया, हसदेश्वर महादेव के मंदिर में दिनभर भक्तिमय वातावरण बना रहा और श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना करते नजर आए,हसदेव के उद्गम स्थल पर आस्था का यह दृश्य लंबे समय तक क्षेत्रवासियों के बीच चर्चा का विषय बना रहा।

सड़क पर बैठे पशुओं के खिलाफ खड़गवां थाना प्रभारी का विशेष अभियान

रात्रि गश्त के दौरान मवेशियों को सड़क से हटाने की पहल हादसों पर लगाम के साथ शराबी वाहन चालकों पर भी नजर

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सड़क पर बैठे आवारा मवेशी और तेज रफ्तार वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शामिल हैं, विशेषकर रात के समय सड़कों पर बैठे पशु वाहन चालकों को दिखाई नहीं देने के कारण अचानक दुर्घटना की स्थिति बन जाती है,इसे देखते हुए खड़गवां थाना प्रभारी द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष पहल शुरू की गई है, पुलिस टीम रात्रि गश्त के दौरान कानून-व्यवस्था पर नजर रखने के साथ-साथ सड़कों पर बैठे और घूम रहे मवेशियों को भी सुरक्षित तरीके से सड़क से हटाने का काम कर रही है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र के संवेदनशील मार्गों,मुख्य सड़कों और ग्रामीण इलाकों में नियमित रात्रि गश्त कर रही है, गश्त के दौरान जहां भी सड़क पर पशु बैठे या घूमते हुए दिखाई देते हैं,पुलिसकर्मी उन्हें सड़क से हटाकर सुरक्षित स्थान की ओर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, पुलिस की इस पहल का उद्देश्य केवल यातायात व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि संभावित दुर्घटनाओं को पहले ही रोकना है।

रात के अंधेरे में मवेशी बनते हैं बड़ा खतरा- ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर रात के समय पर्याप्त रोशनी नहीं होने के कारण सड़क पर बैठे मवेशी वाहन चालकों को दूर से दिखाई नहीं देते,अचानक सामने आने वाले पशुओं से वाहन चालक नियंत्रण खो सकता है, इसका सबसे अधिक खतरा दोपहिया वाहन चालकों को रहता है,कई बार पशु को बचाने के प्रयास में वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर जाते हैं अथवा सामने से आने वाले वाहन से टकराने की स्थिति बन जाती है,ऐसे में खड़गवां पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान पशुओं को सड़क से हटाने की पहल को सड़क सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस की सक्रियता से ऐसे संभावित हादसों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी नजर- रात्रि गश्त के दौरान पुलिस की नजर शराब पीकर वाहन चलाने वाले और तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाने वाले चालकों पर भी है,पुलिस की नियमित मौजूदगी से यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों में कार्रवाई का भय बना हुआ है,सड़क पर मवेशियों के साथ-साथ नशे में वाहन चलाना भी दुर्घटनाओं का बड़ा कारण है,ऐसे में पुलिस दोनों पहलुओं पर निगरानी रखकर सड़क सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।

थाना प्रभारी की पशुपालकों से अपील- थाना प्रभारी ने क्षेत्र के पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने मवेशियों को खुला न छोड़ें और उन्हें सड़क अथवा सड़क किनारे इस तरह न बांधें,जिससे आवागमन प्रभावित हो,उन्होंने कहा कि सड़क पर बैठे पशु किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं,पशुपालकों की थोड़ी सी सावधानी कई लोगों की जान बचा सकती है,पुलिस ने वाहन चालकों से भी रात के समय विशेष सावधानी बरतने,निर्धारित गति से वाहन चलाने और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील की है।

सड़क सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी- खड़गवां पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है,इसमें वाहन चालक,पशुपालक और आम नागरिक सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है,यदि पशुपालक अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें और वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें तो सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

बैकुंठपुर में भूमि रिकॉर्ड दुरुस्ती को लेकर विवाद,एसडीएम न्यायालय ने जारी किया इश्तहार

तरगवां की चार खसरों की जमीन में नाम विलोपन और स्वामित्व को लेकर मामला,पूर्व में व्यवहार न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है विवाद

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

ग्राम तरगवां, तहसील पटना क्षेत्र की भूमि के राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करने और विलोपित किए जाने को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद ने एक बार फिर नया मोड़ लिया है, बैकुंठपुर के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकारों एवं आम लोगों के लिए इश्तहार जारी कर मामले में आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है,दस्तावेज के अनुसार विवादित भूमि के स्वामित्व और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को लेकर मामला व्यवहार न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है और अब राजस्व अभिलेखों में दुरुस्ती का प्रकरण तहसीलदार पटना के समक्ष विचाराधीन है, एसडीएम न्यायालय से जारी इश्तहार में ग्राम तरगवां,तहसील पटना,जिला कोरिया की भूमि से संबंधित मामले का उल्लेख किया गया है,दस्तावेज के अनुसार आवेदक ने दावा किया है कि ग्राम तरगवां स्थित भूमि के खसरा नंबर 143,484,499 तथा 510/2 राजस्व रिकॉर्ड में उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि के रूप में दर्ज रही है। इन जमीनों का कुल रकबा अलग-अलग खसरों के अनुसार 1.160,0.290,0.160 एवं 0.100 हेक्टेयर बताया गया है।

पूर्वजों की मृत्यु के बाद नाम दर्ज होने का दावा- इश्तहार में उल्लेखित दावे के अनुसार आवेदक का कहना है कि संबंधित भूमि उसके पूर्वजों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी, पूर्वजों की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के आधार पर भूमि आवेदक के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुई थी,बाद में हल्का पटवारी स्तर पर हुई कार्रवाई के कारण आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित किए जाने का आरोप लगाया गया है,इसी नाम विलोपन और भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंचा,दस्तावेज में उल्लेख है कि आवेदक ने व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया था,व्यवहार वाद क्रमांक 193/2019 में आवेदक और उसकी बहन रामबाई के संयुक्त स्वामित्व की घोषणा किए जाने का उल्लेख इश्तहार में किया गया है।

जिला न्यायालय से हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला- मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ,दस्तावेज के अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,बैकुंठपुर,जिला कोरिया के समक्ष भी अपील प्रकरण प्रस्तुत हुआ,इसके बाद मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा,इश्तहार में अपील प्रकरण क्रमांक 197/2019 का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि इसके निराकरण के बाद संबंधित पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष भी अपील प्रस्तुत की गई थी,दस्तावेज के अनुसार उच्च न्यायालय बिलासपुर में अपील प्रकरण क्रमांक 110/2019 में आवेदक की अपील निरस्त किए जाने का उल्लेख है,इसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात आवेदक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी अपील प्रस्तुत किए जाने की जानकारी इश्तहार में दी गई है,जो वर्तमान में विचाराधीन बताई गई है।

अब राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती का मामला- इश्तहार में बताया गया है कि उक्त न्यायिक प्रकरणों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती से संबंधित मामला वर्तमान में तहसीलदार पटना के समक्ष विचाराधीन है, प्रकरण की सुनवाई के दौरान विवादित भूमि के रिकॉर्ड में आवेदक के नाम को विलोपित कर अन्य प्रविष्टि किए जाने को लेकर भी आपत्ति सामने आई है,आवेदक द्वारा संबंधित खसरा नंबरों की भूमि को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की बताते हुए राजस्व अभिलेखों में उचित प्रविष्टि किए जाने की मांग की गई है,इस संबंध में एसडीएम न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकारों को सार्वजनिक रूप से सूचना देते हुए आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।

आपत्ति के लिए दिया गया अवसर- जारी इश्तहार में संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों से कहा गया है कि यदि उन्हें इस प्रकरण के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे निर्धारित तिथि के पूर्व स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि/अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किए जाने की बात भी इश्तहार में स्पष्ट की गई है,इस पूरे मामले ने एक बार फिर राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण, उत्तराधिकार और भूमि स्वामित्व से जुड़े मामलों में अभिलेखों की शुद्धता और राजस्व अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं, हालांकि,इश्तहार स्वयं अंतिम स्वामित्व का निर्णय नहीं है,बल्कि संबंधित पक्षों को अपना पक्ष और आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर देने की न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है,मामले में अंतिम स्थिति आगे की सुनवाई और सक्षम न्यायालय/राजस्व अधिकारी के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।

बिहान योजना में लोन वितरण पर उठे सवाल,चारों क्लस्टरों की जांच की मांग

खबर प्रकाशित होने के बाद मची खलबली,ग्राम संगठनों और स्व-सहायता समूहों की फाइलों के साथ एएफएलसीआरपी व पीआरपी की भूमिका जांचने की मांग

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,19 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

आजीविका मिशन 'बिहान योजना' में कथित अनियमितताओं को लेकर खबर प्रकाशित होने के बाद अब योजना के तहत स्व-सहायता समूहों को वितरित किए गए ऋण की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आ गई है,विकासखंड खड़गवां में संचालित चारों क्लस्टरों के ग्राम संगठनों और उनसे जुड़े स्व-सहायता समूहों को दिए गए ऋण की पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठ रही है,मांग है कि ऋण स्वीकृति से लेकर राशि के वास्तविक वितरण और उसके उपयोग तक की पूरी जानकारी का दस्तावेजों से मिलान कराया जाए।

बताया जा रहा है कि यदि चारों क्लस्टरों में ग्राम संगठनवार और समूहवार ऋण वितरण की फाइलों की जांच की जाए तो प्रक्रिया में सामने आने वाली वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है, जांच के दायरे में ऋण प्रस्ताव,समूह की बैठक पुस्तिका, प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया,ऋण आवेदन,बैंक खाते,स्वीकृति आदेश,राशि हस्तांतरण और ऋण के उपयोग से जुड़े दस्तावेजों को शामिल करने की मांग की जा रही है।

लोन वितरण की पूरी प्रक्रिया खंगालने की मांग- सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार,स्व-सहायता समूहों को दिए गए ऋण की जांच केवल कागजी रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहनी चाहिए,प्रत्येक समूह के सदस्यों से सीधे जानकारी लेकर यह पता लगाया जाना चाहिए कि समूह के नाम पर कितनी राशि स्वीकृत हुई, वास्तव में कितनी राशि बैंक खाते में पहुंची और उसका उपयोग किस कार्य के लिए किया गया, इसके साथ ही बैंक खातों के लेन-देन,समूह के रजिस्टर,बैठक पुस्तिका और विभागीय रिकॉर्ड का आपस में मिलान कराने की मांग की जा रही है,यदि रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में अंतर मिलता है तो संबंधित स्तर की जिम्मेदारी भी तय किए जाने की आवश्यकता होगी।

एएफएलसीआरपी और पीआरपी की भूमिका भी जांच के घेरे में- ऋण वितरण की प्रक्रिया में फील्ड स्तर पर काम करने वाले एएफएलसीआरपी और पीआरपी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं,जांच की मांग करने वालों का कहना है कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि समूहों के ऋण प्रकरण तैयार करने और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में किस-किस स्तर के लोगों की भूमिका रही,सवाल यह भी है कि जिन समूहों के नाम पर ऋण स्वीकृत हुआ, क्या वास्तव में उन्हीं समूहों और उनके सदस्यों को राशि मिली? क्या समूह की बैठक में विधिवत प्रस्ताव पारित किया गया था? क्या ऋण की राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया, जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया था?

'लोन की जानकारी मत देना' वाली चर्चा ने बढ़ाए सवाल- इस पूरे मामले में सबसे गंभीर चर्चा यह है कि कुछ फील्ड स्तर पर कार्यरत लोगों द्वारा कथित तौर पर स्व-सहायता समूहों के सदस्यों से कहा जा रहा है कि यदि कोई लोन से संबंधित जानकारी लेने आए तो जानकारी साझा न करें,हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है,लेकिन यदि ऐसा निर्देश वास्तव में दिया गया है तो यह पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है,सरकारी योजना के तहत समूहों को उपलब्ध कराई गई राशि से संबंधित जानकारी जांच से क्यों छिपाई जाए, यह सवाल भी अब उठने लगा है। ऐसे में निष्पक्ष जांच के दौरान समूह के सदस्यों से स्वतंत्र रूप से बयान लेना महत्वपूर्ण होगा।

गांव-गांव जाकर हो भौतिक सत्यापन- जांच की मांग करने वालों का कहना है कि केवल कार्यालय में रखी फाइलों की जांच से पूरी तस्वीर सामने नहीं आएगी, इसके लिए चारों क्लस्टरों के अंतर्गत आने वाले ग्राम संगठनों और स्व-सहायता समूहों का भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए,प्रत्येक समूह से पूछा जाए कि उसे कितनी राशि स्वीकृत हुई, कितनी राशि प्राप्त हुई,राशि का उपयोग कहां किया गया और वर्तमान में ऋण की स्थिति क्या है, बैंक रिकॉर्ड और विभागीय दस्तावेजों से इन बयानों का मिलान कराने पर वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।

प्रशासन के सामने कई सवाल- अब सवाल यह है कि खड़गवां विकासखंड के चारों क्लस्टरों में स्व-सहायता समूहों को अब तक कुल कितनी राशि का ऋण वितरित किया गया? प्रत्येक समूह के ऋण प्रस्ताव और बैंक रिकॉर्ड का सत्यापन कब हुआ? एएफएलसीआरपी और पीआरपी स्तर पर प्रक्रिया में शामिल लोगों की भूमिका की जांच क्यों न कराई जाए? क्या प्रत्येक समूह का गांव-गांव जाकर भौतिक सत्यापन होगा? और यदि किसी समूह के नाम पर ऋण दर्शाया गया हो,लेकिन समूह को राशि प्राप्त ही न हुई हो तो उसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी?

बिहान योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है,ऐसे में ऋण वितरण में किसी भी स्तर की अनियमितता का सीधा असर योजना से जुड़ी महिलाओं पर पड़ता है,अब निगाह प्रशासन की संभावित जांच पर है कि चारों क्लस्टरों की फाइलें खुलेंगी और ऋण वितरण की वास्तविक स्थिति सामने आएगी या मामला केवल कागजी रिकॉर्ड तक सीमित रहेगा।

CMYK

शादीशुदा सुपरस्टार संग लिव इन में आम्रपाली दुबे

भोजपुरी सिनेमा जगत की सबसे लोकप्रिय और सफल जोड़ियों में शुमार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में आ गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर प्रसारित हो रहे चर्चित रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। इस शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सितारों को आमंत्रित कर उनकी पेशेवर जिंदगी के साथ-साथ व्यक्तिगत जीवन से जुड़े बेहद कड़वे और तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। हाल ही में सामने आए एपिसोड में जब भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे इंटरव्यू की चेयर पर बैठीं तो निरहुआ संग उनके रिश्ते पर हुए तीखे सवालों ने माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया।

व्यक्तिगत जीवन के सवालों पर खोया आपा

शो के दौरान एंकर शुभांकर मिश्रा ने आम्रपाली से सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू करते हुए सीधा सवाल किया कि क्या निरहुआ उनके भैया हैं। इस पर आम्रपाली ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे सिर्फ उनके को-एक्टर और अच्छे दोस्त हैं,लेकिन इसके बाद भी एंकर ने उनकी पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाना जारी रखा और पूछा कि वे दोनों आपस में प्यार करने की बात खुलेतौर पर स्वीकार क्यों नहीं कर लेतीं। एंकर ने यहाँ तक दावा कर दिया कि निरहुआ अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते, घर नहीं जाते और आम्रपाली ही उनके बच्चों का ध्यान रखती हैं। अपनी निजी जिंदगी और एक शादीशुदा सह-कलाकार के परिवार पर किए गए इस कमेंट को सुनकर आम्रपाली का धैर्य जवाब दे गया। एंकर के बार-बार तीखे सवाल दागने पर अक्सर शांत रहने वाली आम्रपाली बुरी तरह भड़क गईं। उन्होंने एंकर को बीच में ही रोकते हुए कड़े और सख्त लहजे में हिदायत दी,क्या स्वीकार करना है? आप मेरे बारे में बोलने से पहले जरा सोच लीजिएगा,भक्क...।

आम्रपाली का यह देशी,बेबाक और कड़ा रुख देखकर सेट पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए।

पर्दे की शानदार ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री बनाम रियल लाइफ का सस्पेंस

गौरतलब है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे ने सिल्वर स्क्रीन पर दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में एक साथ काम किया है। जहां एक तरफ दर्शकों के बीच उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ असल जिंदगी में भी उनके अफेयर को लेकर अक्सर तरह-तरह की चर्चाएं उड़ती रहती हैं। हालांकि दोनों कलाकारों ने हमेशा सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे को सिर्फ अपना बेहतरीन दोस्त और सह-कलाकार ही बताया है, लेकिन भोजपुरी बवाल के मंच पर जिस तरह से पर्सनल लाइफ और शादीशुदा जिंदगी को टटोला गया, उसने एक्ट्रेस को काफी असहज कर दिया। इसी शो के दौरान आम्रपाली दुबे, पवन सिंह को मजाकियां अंदाज में प्रपोज भी किया और कहा कि हम साथ मिलकर बच्चे भी पालेंगे।

सोशल मीडिया पर प्रोमो ने मचाया तहलका, दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस वाकये से जुड़ा प्रोमो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया है। प्रोमो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स और फैंस दो धड़ों में बंटे नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ कई लोग एंकर के ऐसे व्यक्तिगत सवालों को सिर्फ शो की टीआरपी बढ़ाने का एक स्टंट बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली के फैंस उनकी निजता का समर्थन करते हुए उनके इस बेबाक जवाब की तारीफ कर रहे हैं। 02 अगस्त 2026 से शुरू हुए इस रियलिटी शो में रोज नए विवाद सामने आ रहे हैं और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में यह ड्रामा क्या नया मोड़ लेता है।

मोहनलाल बड़े पर्दे पर मचाएंगे गदर, 1-2 नहीं 7 फिल्मों का किया ऐलान

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल के चाहने वालों की कमी नहीं है। देश के कोने-कोने में उनके फैन हैं। सिर्फ दक्षिण भारतीय सिनेप्रेमी ही नहीं, बिंदी बेल्ट के दर्शक भी मोहनलाल की फिल्में देखने काफी पसंद करते हैं। मोहनलाल 5 बार नेशनल अवॉर्ड जीत चुके हैं और उनकी फिल्मों को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज बना रहता है। इस बीच मोहनलाल ने एक ऐसा ऐलान किया है, जिससे उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। सुपरस्टार ने एक साथ एक-दो नहीं बल्कि सात फिल्मों का ऐलान किया है, जिसमें मलयालम सिनेमा के कई जाने-माने नाम शामिल हैं। 2026 में मोहनलाल की पहले ही तीन फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और अब उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी।

इन निर्देशकों के साथ करेंगे काम

मोहनलाल ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने उन निर्दशकों के नाम बताए हैं, जिनके साथ वह अपनी आने वाली सात फिल्मों में काम करेंगे। अपने पोस्ट में सुपरस्टार ने लिखा- दिलचस्प कहानियां,रोमांचक सफर और कुछ बेहद खास फिल्ममेकर्स। यहां मेरे आने वाले सात प्रोजेक्ट्स की एक झलक है,जिनके लिए मैं इनके साथ काम कर रहा हूं-विष्णु मोहन,अनूप सत्यन,प्रियदर्शन,दिलेश पोथन,सत्यन अन्थिकाड,जूड एंथनी जोसेफ और जीतू जोसेफ।

मोहनलाल का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो मोहनलाल आखिरी बार जूड एंथनी जोसेफ के निर्देशन में बनी मलयालम फिल्म थुडाक्कम में नजर आए थे,हालांकि फिल्म में उनका कैमियो रोल था। इस फिल्म से मोहनलाल की बेटी विस्मया मोहनलाल ने भी एक्टिंग डेब्यू किया है। मोहनलाल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह तरुण मूर्ति की डायरेक्ट की गई मलयालम कॉप-ड्रामा फिल्म अतिमनोहरम में नजर आएंगे, इस फिल्म में मोहनलाल के साथ जगदीश और मीरा जैस्मीन भी अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में मोहनलाल लौलाजन नाम के पुलिस सब-इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं, जिनकी जिंदगी में पर्सनल और प्रोफेशनल, दोनों स्तरों पर अचानक एक बड़ा मोड़ आता है।

कब रिलीज होगी अतिमनोहरम?

अतिमनोहरम 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की कहानी रतीश रवि ने लिखी है और सिनेमैटोग्राफी शाजी कुमार ने की है। गौरतलब है कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का मुकाबला शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म किंग से होगा। हाल ही में मोहनलाल अपने एक वीडियो को लेकर भी चर्चा में रहे, जिसमें उन्होंने अपने फैंस से माफी मांगी थी। सुपरस्टार ने अपने सिडनी शो मिस होने पर अफसोस जताते हुए बताया कि वीजा के चलते वह इस शो में शामिल नहीं हो सके।

खेल समाचार

टीम इंडिया का नया जादूगर

2 ही टेस्ट मैच और इतने सारे रिकॉर्ड्स, अब भारत को टेस्ट क्रिकेट में रोकना नामुमकिन

गॉल,19 अगस्त 2026। भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को पहले टेस्ट में 165 रनों से हराया। भारत से मिले 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका की पूरी टीम दूसरी पारी में 206 रन बनाकर ऑलआउट हुई। मानव सुथार की घूमती गेंदों का जादू खूब चला और उन्होंने मुकाबले में कुल 10 विकेट चटकाए। मानव सुथार ने पहली पारी में 4 विकेट चटकाए,जबकि दूसरी इनिंग में श्रीलंका के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।

ये रिकॉर्ड हुआ मानव के नाम

मानव ने सिर्फ अपने टेस्ट करियर के दूसरे ही मैच में 10 विकेट लेकर अपना नाम खास लिस्ट में दर्ज करा लिया है। वह भारत की ओर से सबसे कम टेस्ट मैच खेलकर एक ही मुकाबले में 10 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उनसे पहले अक्षर पटेल और लक्ष्मण शिवराम कृष्णन करियर के दूसरे ही टेस्ट में 10 विकेट निकाल चुके हैं। वहीं, नरेंद्र हिरवानी ने अपने टेस्ट डेब्यू मुकाबले में ही 16 विकेट चटकाए थे।

श्रीलंका के खिलाफ 10 विकेट

मानव श्रीलंका के खिलाफ भारत की ओर से एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले यह खास उपलब्धि सिर्फ अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, मनिंदर सिंह, वेंकटपति राजू और रविचंद्रन अश्विन की हासिल कर सके हैं। कुंबले-हरभजन ने 2 बार श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट में 10 विकेट निकाले हैं।

24 साल की उम्र में रिकॉर्ड

मानव सुथार भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में विदेशी सरजमीं पर 10 विकेट चटकाने वाले 7वें स्पिन गेंदबाज बने हैं। हालांकि, वह 28 साल से कम उम्र में यह कारनामा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने 24 साल 16 दिन की उम्र में एक टेस्ट में 10 विकेट चटकाए हैं।

आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में भयंकर उठापटक

आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग एक बार फिर से बदल गई है...ट्रेविस हेड टॉप से सीधे तीसरे नंबर पर चले गए हैं... अब इंग्लैंड के हैरी ब्रूक नंबर एक बल्लेबाज बन गए हैं...भारतीय बल्लेबाजों पर इस बार कोई असर नहीं पड़ा है...

ट्रेविस हेड की बादशाहत खत्म, अब हैरी ब्रूक बना नंबर 1 बल्लेबाज

नई दिल्ली,19 अगस्त 2026। आईसीसी ने अपनी टेस्ट रैंकिंग को फिर से अपडेट कर दिया है। इस बार इसमें जबरदस्त उठापटक नजर आ रही है। ट्रेविस हेड लंबे समय पर नंबर एक बल्लेबाज बने हुए थे,लेकिन अब उनकी बादशाहत खत्म हो गई है। वे अब सीधे नंबर चार पर पहुंच गए हैं। इस बीच इंग्लैंड के हैरी ब्रूक नंबर एक बल्लेबाज बन गए हैं। जो रूट और स्टीव स्मिथ को भी हल्का सा फायदा हुआ है।

हैरी ब्रूक बने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के नंबर एक बल्लेबाज

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अब इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज हैरी ब्रूक नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं। इस बार की रैंकिंग में उन्हें एक स्थान का फायदा हुआ है। उनकी रेटिंग इस वक्त 852 की चल रही है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को भी एक स्थान का उछाल मिला है। वे अब 840 की रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ भी एक पायदान आगे बढ़े हैं। वे नंबर तीन पर आ गए हैं। उनकी रेटिंग फिलहाल 833 की चल रही है।

ट्रेविस हेड टॉप से सीधे नंबर चार पर खिसके

इस बीच लंबे समय से पहले नंबर पर कब्जा जमाए रहे ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को नुकसान उठाना पड़ा है। वे अब तीन स्थानों

के नुकसान के साथ सीधे नंबर 4 पर आकर गिरे हैं। उनकी रेटिंग 819 की रह गई है। साउथ अफ्रीका के टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा 775 की रेटिंग के साथ नंबर 5 पर हैं।

भारतीय टीम के बल्लेबाजों की रैंकिंग में नहीं हुआ कोई बदलाव

इस बीच भारतीय टीम के बल्लेबाजों की रैंकिंग पर कोई भी असर नहीं हुआ है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल 743 की रेटिंग के साथ नंबर 7 पर बने हुए हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल 733 की रेटिंग के साथ नंबर 9 पर हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम भी 716 की रेटिंग के साथ नंबर 10 पर हैं।

अगले अपडेट में बदलेगी टीम इंडिया के प्लेयर्स की रैंकिंग

दरअसल भारत के बल्लेबाजों की रैंकिंग इसलिए नहीं बदली है, क्योंकि भारत बनाम श्रीलंका मुकाबला बुधवार तक चला है, इसलिए इस बार की रैंकिंग में इसे शामिल नहीं किया गया है। रैंकिंग 18 अगस्त तक अपडेट की गई है। अब चूंकि भारत बनाम श्रीलंका मैच खत्म हो गया है, इसलिए अगली जो रैंकिंग जारी की जाएगी, उसमें भारतीय टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज भी इससे प्रभावित होंगे।

न्या0-(पल्लव रघुवंशी) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0

उ0प्र0क0 27/2026
प्रो0न0 319/2026
आगामी पेशी तिथि- 27/08/2026

1.बरखा सेमरिया आ0 राम राजेश उम्र लगभग 30 वर्ष,
2. शीतल आ0 राम राजेश उम्र लगभग 25 वर्ष,
3. नेहा सेमरिया आ0 राम राजेश उम्र लगभग 23 वर्ष,
4. मोना सेमरिया आ0 राम राजेश उम्र लगभग 30 वर्ष,
5. राम राजेश आ0 बिगुराम उम्र लगभग- 52 वर्ष,
सभी निवासी ग्राम माझापारा ग्राम परसोडीखुर्द थाना व तहसील दरिमा सरगुजा (छ0ग0)
.....**आवेदकगण**

प्रति

1.शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक आफ इंडिया, शाखा अम्बिकापुर देवीगंज रोड, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0)
2 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नोडल कार्यालय यूनियन बैंक भवन प्रथमतल 1513/11 अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र. 462001
3 आम जनता, सरगुजा छ0ग0
...**अनावेदकगण**

आवेदन अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम ।

सर्व साधारण आम जनता निवासी ग्राम माझापारा ग्राम परसोडीखुर्द थाना व तहसील दरिमा सरगुजा (छ0ग0) एवं हितबद्ध नागरिकों को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 का वाद प्रस्तुत कर अपनी माता / पत्नी स्व0 कृषा सेमरिया जिनकी नियुक्ति यूनियन बैंक आफ इंडिया नोडल कार्यालय भोपाल म.प्र. के द्वारा यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा अम्बिकापुर में हाउस कीपर के पद पर हुई थी तथा उनकी मृत्यु सेवाकाल के दौरान दिनांक 14.09.2024 को जिला अस्पताल अम्बिकापुर जिला सरगुजा में होना बताते हुए आवेदकगण की माता/पत्नी के मृत्यु उपरांत प्राप्त होने वाले देयको जिसमें नेशनल पेंशन योजना के तहत एन.पी.एस. की राशि जो 10,43,198 रूपये 47 पैसे की राशि तथा उक्त राशि पर प्राप्त होने वाले ब्याज एवं लाभांश 6 अन्य देयक को प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र की मांग की गई है। आम नागरिक को ईस्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि सुनवाई तिथि दिनांक 27/08/2026 को नियत है।

अतः इस ईस्तहार के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि स्व0 कृषा सेमरिया के मृत्यु उपरांत उक्त राशि को प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार किसी व्यक्ति या नागरिक को आपत्ति हो तो वह पेशी तिथि- 27/08/2026 तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। पेशी दिनांक के पश्चात् प्रस्तुत आपत्ति अमान्य होगी और आवेदकगण को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जायेगा, यदि किसी कारण वश उस तिथि को सार्वजनिक अवकाश हो जाता है तो आगामी कार्य दिवस पर प्रकरण की सुनवाई होगी। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से आज दिनांक 08.82026 को जारी किया गया।

अम्बिकापुर
दिनांक - 08.08,2026

(पल्लव रघुवंशी)
न्या0 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी,
अम्बिकापुर,जिला- सरगुजा छ0ग0

सील

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर (छत्तीसगढ़)

नीलाम विज्ञापन

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि बलरामपुर वनमण्डल के अंतर्गत काष्ठागार वाड्रफनगर में रखी इमारती लकड़ी / जलाऊ काष्ठ को निम्नलिखित तिथि व समय में ई-ऑक्शन द्वारा निवर्तन किया जाना है। इच्छुक व्यापारी ई-ऑक्शन में अवश्य भाग लेवें। ई-ऑक्शन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय अथवा काष्ठागार वाड्रफनगर से प्राप्त कर सकते हैं।

डिपो का नाम - काष्ठागार वाड्रफनगर
नीलाम दिनांक - 25-08-2026
नीलाम समय - प्रातः 09:00 बजे से प्रारम्भ

क्र0	वनोपज का विवरण	नया काष्ठ		पुराना काष्ठ	
		लट्ठा	बल्ली /डेंगरी	लट्ठा (घ.मी.)	बल्ली /डेंगरी
		घ.मी.	नग	नग	
1	2	3	4	5	
A	इमारती काष्ठ				
1	सागौन	-	-	95.335	209
2	साल	128.725	67	3762.116	955
3	साजा	-	-	274.072	132
4	तिन्सा	-	-	-	-
5	बीजा, शीशम, खम्हार	-	-	23.004	11
6	हल्दु, मुडी, बांसा	-	-	61.847	4
7	धावड़ा	-	-	18.923	81
8	अन्य मिश्रित (सेमल)	7.673	21	107.376	109
9	नीलगिरी	-	-	2.983	9
10	सलया	-	-	-	-
11	खैर काष्ठ	46.929	-	2.939	-
	योग :–	183.327	88	4348.595	1510
क्र	प्रजाति विवरण				
1	जलाऊ चट्टा मिश्रित प्रजाति सा. 2.00 मी0 X 1.25 X 0.80 मी0	38 चट्टा		605 चट्टा	

टीप –1. केता को ई-ऑक्सन के पूर्व MSTC E-commerce पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
2. क्रेताओं को ई-ऑक्सन के पूर्व कय लॉटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है, सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर 15 प्रतिशत E.M.D. की राशि जमा करना अनिवार्य है।
3. लॉट की थप्पी एवं फोटो MSTC E-commerce पोर्टल में अपने आई डी से लॉगईन करके देख सकते है।

जी.नं.-262702806/2

वनमण्डलाधिकारी
बलरामपुर वनमण्डल,बलरामपुर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा0)मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल,मनेन्द्रगढ़ (छ.ग.)

नीलाम विज्ञापन

सामान्य सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि मनेन्द्रगढ वनमण्डल के अधीनस्थ काष्ठागार मनेन्द्रगढ़ में उपलब्ध नये एवं पुराने ईमारती काष्ठ / जलाऊ काष्ठ का दर्शित तिथि व समय में ई-ऑक्सन द्वारा निवर्तन किया जाना है, इच्छुक व्यापारी ई-ऑक्सन में अवश्य भाग लेवे। ई-ऑक्सन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय अथवा काष्ठागार मनेन्द्रगढ़ से प्राप्त कर सकते है।

डिपो का नाम - काष्ठागार मनेन्द्रगढ़
नीलाम दिनांक - 31-08-2026
नीलाम समय - प्रातः 09:00 बजे से प्रारम्भ

क्र0	प्रजाति	नये काष्ठ		पुराने काष्ठ	
		लट्ठा घ0मी0	बल्ली नग	लट्ठा घ0मी0	बल्ली नग
1	सागौन	0	0	40.974	778
2	साल	59.652	0	2257.486	1791
3	साजा	10.265	0	48.574	120
4	धावड़ा	4.326	0	24.033	321
5	हल्दू	0	0	6.177	10
6	मुंडी	0	0	0.910	0
7	सतकठा	0	0	103.391	64
8	खम्हार	0	0	5.786	22
9	सलैया (सलई)	0	0	3.220	27
10	नीलगिरी	0	0	0.144	0
11	खैर	0	0	3.223	0
	योगः–	74.243	0	2493.918	3133
	जलाऊ काष्ठ				
क्र.	विवरण	नया लॉट		पुराना लॉट	
1	जलाऊ मिश्रित	निरंक		निरंक	
	योग :–	निरंक		निरंक	

टीप –1. केता को ई-ऑक्सन के पूर्व MSTC E-commerce पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
2. क्रेताओं को ई-ऑक्सन के पूर्व कय लॉटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है, सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर 15 प्रतिशत E.M.D. की राशि जमा करना अनिवार्य है।
3. लॉट की थप्पी एवं फोटो MSTC E-commerce पोर्टल में अपने आईडी से लॉगईन करके देख सकते है।

जी.नं.-262702841/2

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल,मनेन्द्रगढ़

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र./अ-20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदकगण श्रीमती संतोष देवी पति स्व0 रामनिवास अग्रवाल,रविन्द्र अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, कमल अग्रवाल आ0 स्व0 रामनिवास अग्रवाल, निवासी सत्तीपारा, अम्बिकापुर,तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा अपने संयुक्त स्वामित्व की मोहल्ला - जूनागढ़ीपारा, नगर अम्बिकापुर शीट नम्बर-08 स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक- 2917 / 8, 2938/8 रकबा 0.02, 0.09 एकड़ भूमि से अपना हक अनावेदक पंकज अग्रवाल आ0 स्व0 बजरंग अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी सदर रोड़, बसंतलाल मार्ग अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के पक्ष में हक त्याग करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु मेन्टनेन्स खसरा की प्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-31/08/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक-14/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण निलेश केडिया, अशेष कुमार केडिया आ.स्व. रामशरण केडिया, दोनों जाति अग्रवाल निवासी वार्ड क्र. 24 भट्ठी रोड़ केदारपुर अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदकगण के पिता द्वारा अपने स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अ0पु0, मोहल्ला देवीगंज रोड़ स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 476/5 रकबा 0.010 ($0.02^{1/2}$ ऐ0) हे0 भूमि के संबंध में पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 28.02.2022 का निष्पादन आवेदकगण के पक्ष में किया गया है। आवेदकगण के पिता रामशरण केडिया की मृत्यु दिनांक 19.03.2026 को एवं उनकी पत्नी भगवती देवी की मृत्यु दिनांक 23.02.2007 को हो गई है। तत्पश्चात आवेदकगण द्वारा वसीयतशुदा भूमि से मृतक रामशरण केडिया का नाम विलोपित करते हुये स्वयं का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदकगण पंजीबद्ध वसीयनामा की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-27/08/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक-07/08/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र.11/अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका रंजीता साहू पति जयप्रकाश साहू, उम्र-45 वर्ष, जाति तेली, निवासी कबीर वार्ड क्र. 43 गेहूं बाड़ी जेल रोड़, अम्बिकापुर के द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदिका के द्वारा अनावेदकगण सविता अग्रवाल पति प्रदीप अग्रवाल, कमला देवी पति डॉ. महावीर प्रसाद अग्रवाल के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अ0पु0, शीट नं. 11 मोहल्ला लखनपुर रोड़ स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 4531/40 रकबा $0.00^{3/4}$ एकड़ (270 वर्गफीट) भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 31.10.2025 के माध्यम से क्रय किया गया है, जिसपर अनावेदिका कमलादेवी द्वारा अपनी सहमति दी गई है। अतः उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर आवेदिका द्वारा क्रयशुदा भूमि का नामांतरण स्वयं के नाम से किये जाने हेतु पंजीबद्ध विक्रय पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 27/08/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक- 11/08/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

मुख्यमंत्री ने 'स्रोत महोत्सव 2026' एवं राज्य स्तरीय कार्यशाला का किया शुभारंभ...

नदी बचेगी तो जल बचेगा और जल बचेगा तो जीवन बचेगा : सीएम साय

- नदियों के उद्गम स्थलों और कैचमेंट एरिया के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक एवं समयबद्ध कार्ययोजना पर जोर
- मानचित्रण,संरक्षण,पुनर्भरण,जनभागीदारी और कार्ययोजना के पांच प्रमुख स्तंभों पर होगा नदी संरक्षण का काम
- नेशनल वाटर एकेडमी पुणे के साथ एमओयू से जल संरक्षण के क्षेत्र में मजबूत होगा क्षमता निर्माण
- एंट्रिक्स कॉरपोरेशन बेंगलुरु के सहयोग से आधुनिक भू-स्थानिक तकनीक का होगा उपयोग

रायपुर,19 अगस्त 2026। नदियां केवल जल का स्रोत नहीं,बल्कि हमारी सभ्यता,संस्कृति,कृषि और समृद्धि की जीवनधारा हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बनाने में प्रदेश की जीवनदायिनी नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिन नदियों ने हमारी सभ्यता को पोषित किया और हमें समृद्धि दी,उनका संरक्षण हम सभी का साझा दायित्व है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के ओमाया गार्डन में आयोजित 'स्रोत महोत्सव 2026' एवं राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेश की नदियों के उद्गम स्थलों एवं जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान और संरक्षण,जल संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने तथा नदी संरक्षण को व्यापक जन अभियान का स्वरूप देना है। कार्यशाला में जल संरक्षण,नदी पुनरुद्धार और जल प्रबंधन से जुड़े विषय विशेषज्ञों के साथ राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के सदस्य तथा विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों द्वारा मंथन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नदी बचेगी तो जल बचेगा और जल बचेगा तो जीवन बचेगा। इसी भावना के साथ राज्य सरकार नदियों के उद्गम स्थलों और कैचमेंट एरिया के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण,आधुनिक तकनीक, पारंपरिक ज्ञान और जनभागीदारी के समन्वय से व्यापक कार्ययोजना पर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक,आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। महानदी सहित प्रदेश की अनेक नदियों ने कृषि, आजीविका और सामाजिक जीवन को समृद्ध किया है। नदियों का अस्तित्व उनके उद्गम स्थलों और कैचमेंट एरिया के स्वास्थ्य पर निर्भर है। इसलिए नदी संरक्षण का कार्य केवल उसके प्रवाह क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकता। हमें नदी के स्रोत से लेकर उसके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को समझकर संरक्षण की समग्र योजना बनानी होगी। उन्होंने कहा कि नदी संरक्षण एवं पुनरुद्धार के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। स्रोत महोत्सव में विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवों के आधार पर ऐसी ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी,जिसे धरातल पर समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।

पांच प्रमुख स्तंभों पर आगे बढ़ेगा नदी संरक्षण अभियान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में नदी संरक्षण के लिए मानचित्रण,संरक्षण,पुनर्भरण,जनभागीदारी और कार्ययोजना के पांच प्रमुख स्तंभों पर काम किया जाएगा। प्रत्येक नदी और उसके जलग्रहण क्षेत्र का वैज्ञानिक तरीके से मानचित्रण किया जाएगा। नदी का उद्गम कहां है,उसके प्रवाह क्षेत्र की प्रकृति कैसी है, भू-उपयोग में किस प्रकार के बदलाव हुए हैं और किन कारणों से नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर प्रभाव पड़ रहा है - इन सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक मानचित्रण और अध्ययन के आधार पर नदी के पूरे इकोसिस्टम के संरक्षण की योजना तैयार की जाएगी। इसमें वन एवं वनस्पति संरक्षण,मृदा क्षरण की रोकथाम,पारंपरिक जल संरचनाओं का संरक्षण एवं पुनर्जीवन,आवश्यकतानुसार नई जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण और भू-जल पुनर्भरण जैसे कार्य शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षाजल हमारे नदी तंत्र और भू-जल का मूल आधार है। इसलिए बारिश के पानी को तेजी से बहकर निकल जाने देने के बजाय उसे अधिक से अधिक मात्रा में धरती के भीतर पहुंचाने के उपाय करने होंगे। इससे भू-जल स्तर में सुधार होगा,जल स्रोतों को पुनर्जीवन मिलेगा और नदियों में लंबे समय तक जल प्रवाह बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

नदी संरक्षण को बनाना होगा जन आंदोलन : मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जल संरक्षण का लक्ष्य केवल सरकारी प्रयासों से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। नदियों के किनारे बसे गांवों और वहां रहने वाले लोगों का नदी से सीधा संबंध है,इसलिए उन्हें नदी संरक्षण की प्रक्रिया का प्रमुख भागीदार बनाना होगा। उन्होंने जिला स्तरीय समितियों के सदस्यों से कहा कि नदियों के किनारे बसे गांवों में स्थानीय समितियां गठित कर पंचायतों के सहयोग से नदी संरक्षण एवं पुनरुद्धार के कार्य आगे बढ़ाए जाएं। स्थानीय समुदाय को नदी की स्थिति,उसके महत्व और संरक्षण के उपायों की जानकारी दी जाए। जब समाज स्वयं अपनी नदी और जल स्रोतों के संरक्षण की जिम्मेदारी लेता है,तब ऐसे प्रयास अधिक प्रभावी और स्थायी होते हैं। मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों से भी आग्रह किया कि जल संरक्षण से जुड़े वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को सरल एवं सहज भाषा में लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि तकनीक तभी सार्थक है,जब उसका लाभ धरातल पर दिखाई दे और आम नागरिक उसे समझकर अपने जीवन में अपना सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। नदियों ने पीढ़ियों से मानव जीवन को जल, भोजन और आजीविका प्रदान की है। इसलिए एक सभ्य समाज के रूप में हमारा दायित्व है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए नदियों और जल स्रोतों को सुरक्षित रखें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि स्रोत महोत्सव 2026 से निकलने वाले निष्कर्ष छत्तीसगढ़ में नदी संरक्षण और जल सुरक्षा की दिशा में एक प्रभावी रोडमैप तैयार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

नीर-नारी-निधि' पुस्तक का विमोचन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में जल संरक्षण पर आधारित 'नीर-नारी-निधि' पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक नीर की रक्षा, नारी की भागीदारी और जल संपदा के संरक्षण की अवधारणा को रेखांकित करती है। पुस्तक में जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण से जुड़े विभिन्न अनुभवों,प्रयासों और नवाचारों का दस्तावेजीकरण किया गया है।

जल संरक्षण और आधुनिक तकनीक के लिए दो महत्वपूर्ण एमओयू

कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण के क्षेत्र में राज्य की संस्थागत और तकनीकी क्षमता को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण एमओयू किए गए। नेशनल वाटर एकेडमी,पुणे के साथ हुए एमओयू के माध्यम से जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और मैदानी अमले के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इससे आधुनिक जल प्रबंधन,नवीन तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों की जानकारी को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार एंट्रिक्स कॉरपोरेशन,बेंगलुरु के साथ हुए एमओयू के माध्यम से इसरो की विशेषज्ञता और आधुनिक भू-स्थानिक तकनीकों का उपयोग जल संसाधनों के वैज्ञानिक विश्लेषण एवं निगरानी में किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में कुनकुरी तहसील के लगभग 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उन्नत भू-स्थानिक तकनीक के माध्यम से जल संसाधनों की स्थिति का अध्ययन,निगरानी और विश्लेषण किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आधुनिक तकनीक से प्राप्त वैज्ञानिक आंकड़ों को स्थानीय अनुभव और पारंपरिक ज्ञान के साथ जोड़कर जल संरक्षण की अधिक प्रभावी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इससे क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप समाधान तैयार करने और उनके परिणामों की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी।

जलस्रोतों की पहचान और संरक्षण भविष्य की जल सुरक्षा के लिए जरूरी : डॉ. विनोद तारे

सीगंगा के संस्थापक एवं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉ. विनोद तारे ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नदियों के उद्गम और उन्हें पोषित करने वाले जल स्रोतों की पहचान एवं संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। बारिश का पानी ही नदियों और भू-जल का प्रमुख आधार है। वर्षाजल के तेज बहाव को नियंत्रित कर उसे अधिक से अधिक मात्रा में जमीन के भीतर पहुंचाना होगा,जिससे भू-जल स्तर बढ़े और भविष्य के लिए जल सुरक्षित किया जा सके। डॉ. तारे ने कहा कि जल संरक्षण के लिए प्राचीन ज्ञान,स्थानीय एवं पारंपरिक अनुभव और आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के बीच समन्वय जरूरी है। इन तीनों को एक साथ जोड़कर तैयार की गई कार्ययोजना ही जल स्रोतों के दीर्घकालिक संरक्षण और जल के सतत उपयोग का आधार बन सकती है।

फायर ब्रिगेड गाड़ियों की खरीदी में हो रही देरी से हाई कोर्ट नाराज...वित्त व गृह सचिव से शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब

बिलासपुर,19 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बेहतर उपाय हेतु चल रही जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आज सख्त रुख अपनाया। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने लगातार यह भरोसा दिलाया है, स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहे हैं। जून में राज्य शासन की ओर से हाई कोर्ट को जानकारी दी गई थी, 124 करोड रुपए की लागत से नए फायर ब्रिगेड गाड़ियों को खरीदने का टेंडर हो चुका है और वह जल्दी ही राज्य में उपलब्ध होगी। बुधवार को जनहित याचिका की सुनवाई के ठीक पहले राज्य शासन ने शपथ पत्र पेश कर बताया, 124 करोड रुपए से गाड़ियों की जो खरीद होनी थी वह अभी भी अटकी हुई है। समय सीमा में वृद्धि और टेंडर में सबसे कम निविदा डालने वाले संस्था के साथ एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने गृह सचिव को पत्र लिखकर जून में, तय समय सीमा को बढ़ाने की अनुमति देने की मांग की थी जो आजतलक नहीं मिल पाई है।

बाइक-स्कूटी की जोरदार भिड़ंत शिक्षक समेत 3 की मौत

कवर्धा,19 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। लोहारा थाना क्षेत्र के बीचारपुर के पास तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि इसमें सरकारी शिक्षक समेत तीन लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, हादसे में श्याम चरण, निवासी ग्राम कापसी, जिला राजनांदगांव की मौके पर ही मौत हो गई। श्याम चरण रणवीरपुर स्थित शासकीय स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। वहीं देवदास मार्कंडेय (18 वर्ष), निवासी ढोढमा नवापारा, ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। तीसरे घायल पुनीत रात्रे (19 वर्ष), निवासी ढोढमा नवापारा, की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही लोहारा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

बीमार माता-पिता से बेटे को अलग करना बहू की क्रूरता....हाईकोर्ट बोला...शादी के बाद जिम्मेदारी खत्म नहीं होती,तलाक की अर्जी मंजूर

बिलासपुर,19 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एनके चंद्रवंशी ने पारिवारिक विवाद और तलाक के मामले में अहम फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद नया परिवार जरूर बनता है, लेकिन इससे बुजुर्ग और बीमार माता-पिता के प्रति संतान की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। अगर पत्नी बिना किसी ठोस और सही वजह के बीमार सास-ससुर को छोड़कर अलग रहने का लगातार दबाव बनाती है, तो उसका यह व्यवहार पति के प्रति मानसिक क्रूरता माना जाएगा। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी है।

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव की नई तारीखों का ऐलान

30 अगस्त से शुरू होगी सदस्यता,29 सितंबर तक चलेगी चुनावी प्रक्रिया

रायपुर,19 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। युवा कांग्रेस की चुनावी सदस्यता और चुनावी प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू होगी और 29 सितंबर शाम 5 बजे तक चलेगी। संगठन ने सभी सदस्यों और चुनाव में शामिल होने के इच्छुक युवाओं से तय समय-सीमा के भीतर जरूरी प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। यह घोषणा ऐसे समय हुई है, जब युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर पिछले कुछ समय से कार्यकर्ताओं के बीच विवाद और शिकायतें सामने आ रही थीं। चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और नियमों को लेकर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व तक शिकायतें पहुंचाई थीं।

यूथ कांग्रेस प्रभारी के छत्तीसगढ़ दौरे का आखिरी दिन : इसी विवाद के बीच युवा कांग्रेस प्रभारी स्मृति रंजन लेंका 17 से 19 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं।

आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया से प्रभावित कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनी गईं। चुनाव में सामने आई कथित अनियमितताओं, नियमों में बदलाव और अब तक हुई कार्रवाई को लेकर भी कार्यकर्ताओं से जानकारी ली गई।

राजीव भवन में हुई कार्यकर्ताओं से चर्चा

17 अगस्त को रायपुर के राजीव भवन, शंकर नगर में प्रदेश प्रभारी स्मृति रंजन लेंका और चुनाव पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसमें चुनाव प्रक्रिया से प्रभावित कार्यकर्ताओं ने अपनी शिकायतें और आपत्तियां राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखीं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने शिकायतों को समझने के साथ इनके निराकरण को लेकर आगे की कार्रवाई पर भी चर्चा की।

मीडिया में मामला उठा तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया संज्ञान

युवा कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया को लेकर कार्यकर्ताओं ने जो सवाल उठाए थे,उन्हें मीडिया में भी प्रमुखता से जगह मिली। इसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने मामले का संज्ञान लिया और पदाधिकारियों को छत्तीसगढ़ भेजकर सीधे कार्यकर्ताओं से बात करने का फैसला किया। अब नई चुनावी समय-सारिणी की घोषणा के बाद संगठन के सामने चुनौती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी प्रक्रिया कराने की है। 30 अगस्त से शुरू होने वाली चुनावी प्रक्रिया 29 सितंबर शाम 5 बजे तक चलेगी।

'पुष्पा' स्टाइल में हो रही थी तस्करी : ट्रक के टायर में मिला 70 लाख से ज्यादा का गांजा,दो तस्कर गिरफ्तार

गरियाबंद,19 अगस्त 2026। 'ऑपरेशन निश्चय' अभियान के तहत गरियाबंद पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो फिल्म पुष्पा स्टाइल में गांजा की तस्करी कर रहे थे। ट्रक के टायर के अंदर से 70 लाख से ज्यादा का गांजा बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक, 19 अगस्त को थाना देवभोग पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक मेटाडोर में अवैध रूप से गांजा लेकर देवभोग की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर खुटगांव अंतरराज्यीय पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात जवान संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान

मेटाडोर को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मेटाडोर के छह टायरों के अंदर फिल्मी अंदाज में छिपाकर रखा गया 151.50 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 75 लाख 50 हजार रुपए आंकी गई। पुलिस ने मौके से मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के रोहित पांडेय और ओडिशा के कालाहांडी जिले के रमेश नायक को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से गांजा के अलावा करीब 20 लाख 25 हजार रुपये कीमत का मेटाडोर वाहन भी जब्त किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(सी) और 27ए के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। गरियाबंद पुलिस के अनुसार, 'ऑपरेशन निश्चय' के तहत पिछले आठ महीनों में 44 प्रकरण दर्ज कर 86 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान कुल 10 क्विंटल 80 किलोग्राम यानी 1,080 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ 17 लाख रुपये है।

इसके अलावा गांजा तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 32 वाहन भी जब्त किए गए हैं, जिनमें 18 दोपहिया और 14 चारपहिया वाहन शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गरियाबंद जिला कई राज्यों की सीमा से लगा होने के कारण तस्कर यहां से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का प्रयास करते हैं।

दिमागी नक्सली वाले बयान के लिए पीएम मोदी और बीजेपी मांगे माफी : दीपक बैज

रायपुर,19 अगस्त 2026। पीएम मोदी के दिमागी नक्सली वाले बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है. दीपक बैज ने इस बयान के लिए भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी से मांफी मांगने की मांग की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर देश के युवाओं को दिमागी नक्सली कहा है. भाजपा नक्सलवाद का ज्ञान दे तो बेहतर होगा. क्योंकि नक्सलवाद का दर्द सबसे ज्यादा कांग्रेस ने ही झेला है. वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस की भूमिका पर बहस के लिए विधायक अजय चंद्राकर की चुनौती को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने स्वीकार कर लिया है। बैज ने कहा कि अजय चंद्राकर को भी हमारी ओर से खुली चुनौती है। उन्होंने कहा कि बहस से पहले चंद्राकर जवाब दें कि 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? तिरंगे को भाजपा के पूर्वजों ने अशुभ क्यों कहा था? रायपुर में कमल विहार फेस-2 प्रोजेक्ट लाने की सरकार की तैयारी को लेकर दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का उद्देश्य गरीबों को आवास देना नहीं है, बल्कि योजना को ऐसे इलाके में ले जाना है, जहां बड़े नेताओं, उनके करीबियों और अधिकारियों की जमीनें हैं। बैज ने कहा कि सरकार जमीनों के दाम बढ़ाने और सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना से गरीबों को कोई फायदा नहीं होगा।

बच्चों की जान से खिलवाड़! मिड-डे मील में मिली डामर गोली

28 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत,शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

बेमेतरा,19 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के आत्मानंद उत्कृष्ट कन्या शाला में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब स्कूल में परोसे गए मध्यान्ह भोजन में डामर की गोली मिलने की बात सामने आई। खाना खाने के बाद कई छात्राओं ने पेट दर्द की शिकायत की। मामला सामने आते ही स्कूल प्रबंधन में अफरा-तफरी मच गई और आनन-फानन में छात्राओं को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की

जानकारी ली। फिलहाल 28 छात्राओं का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। मामले में स्कूल के प्रधान पाठक ने बताया कि बच्चों ने मध्यान्ह भोजन में डामर की गोली की स्मेल आने की जानकारी दी। इसके बाद बच्चों को खाना खाने से मना किया गया। उन्होंने बताया कि बच्चों को खाना खिलाने से पहले रसोइया से खाना खिलाकर उसकी जांच की जाती है। आज भी शासन के निर्देशानुसार एक रसोइया ने खाना खाकर जांच की थी। हालांकि, उनके द्वारा कुछ भी गड़बड़ नहीं होने की सूचना दी गई, जिसके बाद बच्चों ने खाना खाया।

CG IPS पोस्टिंग...साइबर क्राइम से निपटने PHQ में बना 'S4C : आईजी प्रशांत कुमार अग्रवाल और DIG गिरिजा शंकर जायसवाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

रायपुर,19 अगस्त 2026। साइबर अपराधों को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में स्टेट साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया गया हैं। आईजी प्रशांत कुमार अग्रवाल को एसी4सी का प्रमुख बनाया गया हैं। वहीं, डीआईजी गिरिजा शंकर जायसवाल को भी जिम्मेदारी दी गई हैं। यह वर्टिकल पुलिस मुख्यालय की तकनीकी सेवाएँ शाखा के अधीन कार्य करेगा। बता दें कि बढ़ते साइबर अपराधों की निगरानी के लिए 'एसी4सी' का गठित हुआ है। स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र) राज्यों में साइबर अपराधों से निपटने, उनकी निगरानी करने और केंद्रीय एजेंसी एसी4सी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए बनाई गई इकाई है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)